लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 240

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

"गलतियाँ करने से मत डरिए, क्योंकि वही आपको उस जगह तक ले जाती हैं जहाँ जीत आपका स्वागत करती है।"

TODAY WEATHER

DAY	NIGHT
42°	26°
Hi	Low

संक्षेप

आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर पथराव, कार के शीशे तोड़े, इलाके में तनाव

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान आसनसोल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में हिंसा की खबर सामने आई। यहां से भाजपा की उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अग्निमित्रा पॉल को निशाना बनाया गया। चुनावी ड्यूटी के दौरान जब वे क्षेत्र का दौरा कर रही थीं, तब उनकी कार पर जबरदस्त पथराव किया गया। इस हमले में उनकी गाड़ी के पीछे के खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। यह घटना आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहमत नगर इलाके के पास हुई। पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार, अग्निमित्रा पॉल एक मतदान केंद्र का मुआयना करने के बाद वहां से निकल रही थीं। जैसे ही उनकी चलती हुई कार सड़क पर आगे बढ़ी, अज्ञात लोगों ने गाड़ी को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरों की चोट इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के पिछले हिस्से के कांच पूरी तरह टूट गए। अग्निमित्रा पॉल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब वह पोलिंग बूथ से बाहर आ रही थीं, तभी उनकी चलती गाड़ी पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला चुनाव को प्रभावित करने और मतदाताओं को डराने की एक सोची-समझी साजिश है। अग्निमित्रा पॉल ने इस घटना के पीछे सीधे तौर पर अपने राजनीतिक विरोधियों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि इस हमले के पीछे कौन है और कौन चुनाव में धांधली करना चाहता है। भाजपा उम्मीदवार ने इस हमले की आधिकारिक शिकायत चुनाव अधिकारियों और स्थानीय पुलिस से की है।

टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच झड़प, देसी बम से भी हमला, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है?

नई दिल्ली। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। इस बीच मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान लाठियां चलीं और पत्थर भी फेंके गए। इससे पहले, मुर्शिदाबाद जिले के नउदा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार रात बमबाजी हुई। तृणमूल कांग्रेस सांसद अबू ताहेर खान ने इसके पीछे हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के लोगों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को भयभीत करने के लिए हुमायूं की पार्टी के लोगों ने बमबाजी की है। चुनाव आयोग ने इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। एक चश्मदीद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मैं कल रात लगभग 8 बजे नमाज पढ़ने के लिए बाहर आया। मैं खड़ा था और दो लड़के आए और मेरे पैर के नजदीक बम फेंक दिया। हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह सब किया है।' हुमायूं कबीर ने कहा, 'नउदा, रेजीनगर और मुर्शिदाबाद की सभी 22 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। लेकिन नउदा के दो बूथों पर 9 और 10 यहां रात में कुछ घटना घटी है। उन लोगों ने पुलिस का बैग छीन लिया।' वहीं, रायपुर गांव के निवासियों ने दावा किया कि सुबह से ही वहां हथियारबंद लोग मौजूद थे, जिससे डर का माहौल बन गया था।

'झालमुरी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी..., पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का अटैक, सीएए पर दिया बड़ा आश्वासन

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आलोचना करते हुए कहा कि उनके द्वारा हाल ही में झालमुरी के सेवन से सत्तारूढ़ पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। 23 अप्रैल, 2026 को कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठियों को पनाह देने और महाजंगल राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और मतुआ और नामाशूद्र समुदायों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी वादा किया।

रैली में मोदी ने कहा कि आपको भाजपा-एनडीए की जीत का झंडा पूरी ताकत से लहराना चाहिए। 4 मई को बंगाल में भी भाजपा की जीत का जश्न मनाया जाएगा, मिठाइयाँ बाँटी जाएँगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। झालमुरी ने कुछ लोगों को करारा झटका भी दिया है। मैंने झालमुरी खाई, लेकिन उसका तीखापन टीएमसी को लगा। यह टिप्पणी 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में उनके द्वारा साझा किए गए एक हल्के-फुल्के पल की ओर इशारा करती है, जहाँ उन्होंने चुनावी रैलियों की एक श्रृंखला के बाद झालमुरी खाई थी।

मोदी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन पर टिप्पणी करते हुए टीएमसी के मौजूदा विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि पंद्रह साल पहले लोग कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। आज वे टीएमसी के जंगल राज के खिलाफ खड़े हैं। उत्पीड़कों और भ्रष्ट लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। आप हमारा नारा जानते हैं, 'सबका साथ, सबका विकास'। लेकिन टीएमसी 'घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास' में विश्वास करती है। वे उन्हें पनाह देते हैं। 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में सुशासन की एक नई गारंटी शुरू होगी।

उन्होंने आगे आश्वासन देते हुए कहा कि मैं यह आश्वासन देने आया हूं कि मतुआ समुदाय, नामाशूद्र समुदाय और शरणार्थी परिवारों को टीएमसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो भी भारत में शरण और सम्मान की तलाश में आया है, मोदी उनके साथ खड़े हैं। सरकार बनने के बाद, सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। आपको वे सभी अधिकार और लाभ मिलेंगे जिनके प्रत्येक भारतीय नागरिक हकदार हैं। यह मोदी का आश्वासन है।

अब स्वदेशी 'पिनाका' बनेगा रॉकेट आर्टिलरी की बड़ी ताकत, पुराने रूसी 'Grad' की लेगा जगह

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय सेना अपनी युद्धक क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सेना ने अब पुराने रूसी मूल के BM-21Grad रॉकेट लॉन्चरों को पूरी तरह से सेवा से हटाने और उनके जगह पर स्वदेशी पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव का उद्देश्य न केवल आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, बल्कि युद्ध के मैदान में सटीक मारक क्षमता को सुनिश्चित करना भी है। सैन्य सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना की योजना पिनाका की कुल 22 रेजिमेंट तैयार करने की है। सेना इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और लक्ष्य रखा गया है कि मध्य-2026 तक 10 पिनाका रेजिमेंट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएं।

परिसीमन के 'नाटक' से ध्यान भटका रही भाजपा, फ्यूल-फर्टिलाइजर संकट पर खरगे ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारतीय सरकार पर देश के ईंधन और उर्वरक आपूर्ति को सुरक्षित करने में विफल रहने और परिसीमन के नाटक के माध्यम से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत का ईंधन उत्पादन कम हो गया है, आयात विविधीकरण लड़खड़ा गया है, और होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले 14 जहाज फंसे हुए हैं। खरगे ने X पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने परिसीमन के हथकंडों के जरिए अपनी विफलताओं और एपस्टीन फाइल के गंभीर आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इस दिखावे को भांप लिया। भाजपा देश के लिए ईंधन और उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल रही है। खरगे ने आगे कहा कि उत्पादन में गिरावट आई है, आयात विविधीकरण विफल रहा है, होर्मुज जलडमरूमध्य में हमारे जहाजों को सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। भारतीय ध्वज वाले 14 जहाज 54 दिनों से वहां फंसे हुए हैं। मोदी सरकार की वजह से भारत का कच्चा तेल उत्पादन 2025-26 में लगातार 11वें वर्ष गिर रहा है। कुल कच्चे तेल उत्पादन में 2014-15 से लगभग 22% की गिरावट आई है। खरगे ने आगे बताया कि गैस उत्पादन में लगभग 40% की गिरावट आई है, जो 2011-12 में 47,555 मिलियन माइक्रोमीटर सेमी (MMSCM) से गिरकर 2020-21 में 28,672 मिलियन माइक्रोमीटर सेमी (MMSCM) हो गया है। उर्वरक भंडार के बारे में उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पहले भी, कई मौसमों में उर्वरक की कमी की खबरें आ रही थीं।

पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच सुवेंदु की टीएमसी को सीधी चेतावनी- 'जो शांति तोड़ेगा...'

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव नियमों का उल्लंघन करने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कड़ी चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान जारी है। नंदीग्राम और भाबनीपुर से भाजपा के उम्मीदवार अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं।

भाजपा नेता के अनुसार, सत्ताधारी टीएमसी मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है, खासकर हिंदुओं को। उन्होंने दोहराया कि वे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं और कहा कि अपराधी टीएमसी के लोग हैं, जो एक विशेष समुदाय से आते हैं। अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मुझे इस मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। आम आदमी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, शांति चाहता है। गुंडे लोगों को लूट रहे हैं। जो शांति तोड़ेगा हम उसे तोड़ने का काम करेंगे।

अधिकारी की धमकी के जवाब में, टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में पुलिस भाजपा के पक्ष में काम कर रही है; हालांकि भगवा पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी ने इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से भी शिकायत की है, और टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से मुलाकात कर दो पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन अधिकारियों की मौजूदगी मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी नंदीग्राम सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मामूली अंतर से हराया था, जिसके चलते ममता बनर्जी को भाबनीपुर से उपचुनाव के जरिए राज्य विधानसभा में निर्वाचित होना पड़ा था।

पांच साल बाद चीन के पर्यटकों को वीजा जारी करेगा भारत, गलवान झड़प के बाद से बंद थे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत सरकार चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। करीब पांच साल पहले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इन सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है।

यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे आ रही नरमी के बीच उठाया गया है। हाल ही में भारत और चीन ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही लंबे समय से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी दोबारा बहाल कर दिया गया है। नए वीजा नियम मुख्य चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे।

'पीएम मोदी का विरोध कर विपक्ष बना महिला विरोधी', महिला आरक्षण बिल पर भाजपा का बड़ा बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को विपक्षी दलों पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्रतिरोध तेजी से महिलाओं के विरोध के रूप में देखा जा रहा है, या जिसे उन्होंने आधी आबादी कहा। नितिन नबीन ने कहा कि मोदी जी ने आधी आबादी को, देश की माताओं-बहनों को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान देने का काम किया, और अब महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए उनकी हिस्सेदारी की बात की। महिला आरक्षण एक बड़ा मौका था- हमारी माताओं-बहनों को हिस्सेदारी देने का।

नबीन ने आगे कहा कि लेकिन हमें दुख है कि विपक्ष के विरोध के कारण ये हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिल सकी। लेकिन ये तय है कि भाजपा ने जब भी संकल्प किया है और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने हमेशा अपने संकल्प को पूरा किया है। हम सब की इच्छा थी कि 2029 लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं को एक बड़ी हिस्सेदारी में जोड़ पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी का विरोध करते करते विपक्षी दल देश की आधी आबादी, माताओं-बहनों के विरोध में खड़े हो गए। नितिन नबीन ने कहा कि जहां तक साउथ की बात है तो वहां के लोगों के हक मारने का काम भी कांग्रेस-डीएमके ने किया। पूरे साउथ को परेशानी में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। हम भारत के नागरिकों के साथ खड़े हैं, विदेशी घुसपैठियों के साथ नहीं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए चार महीने का पर्याप्त समय दिया था। यदि कोई गड़बड़ी थी, तो उसे तब उठाया जाना चाहिए था, लेकिन वे केवल प्रक्रिया को बाधित करना चाहते थे।

कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भेजा सख्त नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही का वीडियो प्रसारित करने के संबंध में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से संबंधित सभी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। यह मामला आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल स्वयं अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे।

अदालत ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के वीडियो प्रसारित करने से न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए ऐसी सामग्री को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। आबकारी मामले में न्यायाधीश परिवर्तन की मांग वाली केजरीवाल की याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के बयान और अदालत की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने वाले वीडियो को हटाने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत अरोरा की खंडपीठ ने पारित किया। वीडियो में केजरीवाल न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष मामले से खुद को अलग करने के अपने अनुरोध को लेकर बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे।

इससे तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा हो सकती है... आई-पीएसी रेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कोलकाता, एजेंसी। कोलकाता I-PAC ED रेड मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम दे सकता है क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ईडी ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का दावा नहीं है।

जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने का दावा नहीं कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि ईडी का तर्क I-PAC मामले में कानून के शासन के उल्लंघन का था। इसके साथ ही इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

ममता की दखलंदाजी पर SC सख्त

ED की ओर से SG तुषार मेहता दलील पेश करते हुए कहा कि कल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस ने बहस पूरी कर ली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ED रेड में पहुंचकर दखल देने पर कल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में जाकर दखल देता है तो इसे सिर्फ केंद्र या राज्य के बीच विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी ममता सरकार की इस दलील पर सवाल उठाते हुए की थी, जिसमें उन्होंने इस केस में ED की याचिका पर सवाल खड़ा किया था। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच मामसे की सुनवाई कर रही थी।

अनुच्छेद 32 बनाम 131 की कानूनी बहस

ममता सरकार का कहना था कि इस केस में आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन का दावा करने वाली ED की याचिका सुनवाई लायक नहीं है चूंकि यह राज्य बनाम केंद्र सरकार का मसला है, इसलिए इसमें आर्टिकल 131 के तहत याचिका दायर होनी चाहिए।

व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी स्वीकार नहीं की जा सकती... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

नई दिल्ली, एजेंसी। सबरीमाला रेफरेंस सुनवाई के आठवें दिन न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल के इस निवेदन के जवाब में की गई कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता को स्रोत की परवाह किए बिना स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। कौल ने एक अखबार में डॉ। शशि थरूर द्वारा लिखे गए लेख का हवाला दिया था, जिसमें धार्मिक राहत के मामलों में न्यायिक संयम बरतने की अपील की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हालांकि न्यायालय सभी प्रख्यात लेखकों और विचारकों का सम्मान करता है, लेकिन यह लेख अंततः एक व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत राय तो व्यक्तिगत राय ही होती है, यह संकेत देते हुए कि इसका न्यायालय पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता। कौल ने उत्तर दिया कि सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। यदि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी स्रोत, किसी भी देश, किसी भी विश्वविद्यालय से आती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम एक सभ्यता के रूप में इतने समृद्ध हैं कि हम ज्ञान और सूचना के सभी रूपों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते। इस दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी, जो इस बहस के लिए वास्तव में अप्रासंगिक है। यह जस्टिस नागरत्ना ने तब कहा, जब कौल ने कहा कि मुद्दा सिर्फ इतना है कि ज्ञान और सूचना जहां से भी आए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कौल दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया की ओर से बहिष्कार की प्रथा को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में पेश हो रहे हैं।

कौल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 26(ख) के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों को सभी संदर्भों में अनुच्छेद 25(2)(ख) के अनुसरण में राज्य द्वारा अपनाए गए सामाजिक सुधार कानूनों के अधीन नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि देवरू फैसले में यह सामान्य नियम नहीं दिया गया है कि अनुच्छेद 26(घ) सभी संदर्भों में अनुच्छेद 25(2)(ख) के अधीन हो, जैसा कि यह मामला केवल मंदिर प्रवेश के संदर्भ में था। उन्होंने अनुच्छेद 26(ख) और 25(2)(ख) के सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकालने की वकालत की।

11 लाशों का पोस्टमार्टम: चार वाहनों में 10 मिनट तक चीखते रहे, हड्डियां तक जल गईं, बच्चों के शव देख आंखें नम

आर्यावर्त संवाददाता

मिर्जापुर। बीती रात रीवा-मिर्जापुर हाईवे पर स्थित ड्रमंडगंज घाटी में हुए दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों समेत 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ तभी से कार में सवार लोग चीखने-चिल्लाने लगे थे। फिर तेज धमाके के साथ स्विफ्ट कार और बोलेरो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जब तक हम लोग बचाने की कवायद शुरू करते तब तक कार में बैठे लोगों की चीखने की आवाजें थम गईं।

गुरुवार की सुबह सभी 11 लोगों की लाशों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। एक-एक कर गठरी में रखे शवों को बाहर निकाला गया। जब बच्चों की लाशें निकलीं तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े लोगों की भी आंखें नम हो गईं। आग में जलने से अधिकांश शव के कुछ अंश ही बचे हुए थे। वहीं, अजीज खान (46) की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

रीवा-मिर्जापुर हाईवे पर स्थित ड्रमंडगंज घाटी में बुधवार की रात करीब आठ बजे भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक, ट्रेलर, स्विफ्ट कार और बोलेरो की आपस में टक्कर के बाद बोलेरो में आग लग गई, जिससे उसमें सवार नौ लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा स्विफ्ट कार चालक और ट्रक के खलासी की भी मौत हो गई। हादसे के बाद घाटी क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, ड्रमंडगंज घाटी में गिट्टी लदा ट्रेलर नीचे उतर रहा था। उसके पीछे स्विफ्ट कार चल रही थी, जबकि कार के पीछे दाल लदा ट्रक और उसके पीछे बोलेरो वाहन आ रहा था। इसी दौरान दाल लदे ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया और उसने आगे चल रही स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्विफ्ट कार आगे ट्रेलर से जा भिड़ी। वहीं पीछे से आ रही बोलेरो भी अनियंत्रित होकर ट्रक में टकरा गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो में तुरंत आग लग गई। देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। ट्रक चालक किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन बोलेरो सवारों को निकलने का मौका नहीं मिल सका।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर ड्रमंडगंज, हलिया समेत आसपास के थानों की पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचीं। आग बुझाने के लिए दमकल की दो गाड़ियां घंटों तक मशक्कत करती रहीं, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।

आग बुझने के बाद बोलेरो से नौ शव बरामद हुए, जिनमें दो महिलाएं, दो बच्चे और पांच पुरुष शामिल हैं। सभी शव बुरी तरह जल चुके थे, जिससे उनकी पहचान करने में दिक्कत हो रही है। वहीं हादसे में स्विफ्ट कार चालक जयप्रकाश (26) पुत्र मुन्नर, निवासी परसिया दुबे, राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) की भी मौत हो गई। इसके अलावा ट्रक के खलासी की भी जान चली गई।

सूचना पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक और क्षेत्राधिकारी लालगंज अमर बहादुर समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है, जिससे एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए और बोलेरो में आग लग गई।

फिलहाल पुलिस सभी शवों को कब्जे में लेकर उनकी शिनाख्त कराने में जुटी है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के अन्य कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।

सीओ लालगंज अमर बहादुर ने बताया कि बोलेरो में सवार प्रियंका सिंह (42) पत्नी कमलेश निवासी सतना, कार्तिकेय सिंह (19) पुत्र कमलेश निवासी सतना, पीयूष सिंह (14) पुत्र प्रदीप निवासी रामपुर हंसवार थाना जिगना, पंकज सिंह (40), बीना सिंह (47) पत्नी प्रदीप, वंदना सिंह (43) पत्नी अरुण, शिवा सिंह (8) पुत्र अरुण, सोनम सिंह (9) पुत्री अरुण, बोलेरो चालक विष्णु सिंह (45) पुत्र ठिक्कर, निवासी रामपुर हंसवार थाना जिगना है। ट्रक खलासी विकाश शर्मा (32) पुत्र ओमकार निवासी नया खेड़ा सागर मध्य प्रदेश, कार चालक जय प्रकाश (28) पुत्र मुन्नर निवासी परसिया राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) रहे।

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि हादसे के बाद चारों वाहनों की पहचान हो गई है। जिसमें एक ट्रक बिहार का है। दूसरा ट्रक मध्य प्रदेश का है। कार सोनभद्र की है। बोलेरो मिर्जापुर की है, जिसकी छानबीन की जा रही है। कुछ परिजनों से संपर्क हुआ है।

हादसे में मरने वाले कि संख्या हुई 12, ट्रक चालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

ड्रमंगगंज घाटी में ट्रक, कार, बोलेरो की भीषण टक्कर में मौत की संख्या अब 12 हो गई है। अस्पताल में भर्ती तक चालक की बृहस्पतिवार की सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार नौ लोगों की जलकर मौत हुई थी। इसके अलावा स्विफ्ट कर चालक जयप्रकाश व चना-दाल लदे ट्रक के खलासी विकास शर्मा की मौत हुई थी।

घायल ट्रक चालक अजीज खान (46) निवासी बेहना मध्य प्रदेश को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान बृहस्पतिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि ट्रक चालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

मरीजों की सेहत से खिलवाड़! बिना डिग्री व मानक के चल रहे हॉस्पिटल-क्लिनिक

सुल्तानपुर। जनपद में इन दिनों इलाज कम और खिलवाड़ ज़्यादा हो रहा है। शहर से लेकर कस्बों तक फर्जी हॉस्पिटल, क्लिनिक और पैथोलॉजी सेंटरों का ऐसा जाल फैल चुका है, मानो बिना डिग्री के डॉक्टर बनना अब सबसे आसान रोजगार हो गया हो। सवाल यह है कि क्या मरीजों की जान अब प्रयोगशाला बन चुकी है। हकीकत यह है कि इन तथाकथित स्वास्थ्य केंद्रों में न तो योग्य डॉक्टर हैं, न ही जांच के मानक उपकरण, और न ही साफ-सफाई का कोई नामोनिशान। एक ही कमरे में क्लिनिक भी चल रहा है और पैथोलॉजी भी जैसे इलाज नहीं, कोई किराना दुकान हो। झोलाछाप विशेषज्ञ मरीजों की नब्ज से ज्यादा जेब टटोलने में माहिर नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कई मामलों में फर्जी जांच रिपोर्ट के आधार पर इलाज किया जा रहा है।

एटीएम धोखाधड़ी व चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी और एटीएम धोखाधड़ी की वारदातों में शामिल एक अंतरजनपदीय गिरोह के तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, ₹24,400 नकद और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अखण्ड प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गुरुवार सुबह करीब 05:35 बजे पुलिस टीम ने सौरमऊ बाईपास सर्विस लेन के पास दबिश देकर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आकिब, मोहम्मद सारिफ और मोहम्मद फरहान जो जनपद प्रतापगढ़ के निवासी हैं, विभिन्न थानों में दर्ज कई मामलों में वांछित चल रहे थे। इन पर सुलतानपुर के कोतवाली नगर, गोसाईगंज और बंधुआकलां थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये लंबे समय से चोरी व एटीएम धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। इस सफल कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार राय, उप-निरीक्षक जितेन्द्र यादव, पंकज कुमार, वैभव त्रिपाठी समेत कांस्टेबल रजत सचान और दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है।

आग से धधक रही थी गाड़ियां, चिल्ला रहे थे लोग... मिर्जापुर हादसे में जान गंवाने वाले 11 कौन?

आर्यावर्त संवाददाता

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने हिलाकर रख दिया है। अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का घुमान मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मध्य प्रदेश की ओर से चना लादकर आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका। बेकाबू ट्रक ने सबसे पहले सामने चल रही बोलेरो को जोरदार टक्कर मारी, फिर एक ऑल्टो कार को रौंदते हुए आगे खड़े डंपर से जा भिड़ा।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो और ऑल्टो कार में तुरंत आग लग गई। वाहन में सवार लोगों को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल पाया और वे जिंदा जल गए। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि कोई भी वाहन के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोग अपनी आंखों के सामने यात्रियों को तड़पते हुए देखते रहे, वे चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके।

स्थानीय लोगों के अनुसार, फायर ब्रिगेड को सूचना देने के करीब आधे घंटे बाद टीम मौके पर पहुंची। तब तक आग पूरी तरह विकराल रूप ले चुकी थी और सभी लोग जलकर दम तोड़ चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

हादसे में मरने वालों में बोलेरो सवार 9 लोग शामिल हैं, जो मैहर से दर्शन कर लौट रहे थे। इनमें एक ही परिवार के मां, बेटा और बेटी के अलावा दूसरे परिवार के मां-बेटे की भी मौत हुई है। इसके अलावा एक अन्य कार सवार व्यक्ति की भी जलकर मौत हो गई, जबकि ट्रक का खलासी केबिन में फंसने के कारण जान गंवा बैठा। इस तरह कुल 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

शव बुरी तरह झुलस चुके थे

मृतकों की पहचान में काफी दिक्कतें आईं, क्योंकि शव बुरी तरह झुलस चुके थे। बाद में परिजनों ने घटनास्थल और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर अपने प्रियजनों की पहचान की। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है, वहीं परिजन अपने प्रियजनों के शव लेकर घर लौट रहे हैं। बोलेरो में सवार वीना सिंह, इनका बेटा पीयूष सिंह, बेटी सोनम की मौत हुई है। वहीं, पंकज सिंह, वंदना सिंह और शिव सिंह की भी मौत हुई है। ये सभी मिर्जापुर के रहने वाले थे।

'जिम मत जाया करो, लेकिन वो मानती नहीं थी', नाराज कारोबारी ने पत्नी का किया कत्ल, इसलिए बेड पर डाल दी लाश

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में डबल फाटक के पास बुधवार को जिम जाने से नाराज स्क्रैप व्यापारी शोभित गुप्ता ने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता (35) की शटर खोलने वाले हैंडल से सिर पर हमला कर हत्या कर दी। इस वारदात को सुबह दस बजे अंजाम दिया। उसने हत्या की वारदात को हादसा दर्शाने की भी कोशिश की।

पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी कि उसकी पत्नी गिरकर घायल हो गई है। बहुत खून बह रहा है, लेकिन हालात देखकर पुलिस को शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना कबूल लिया। उसका कहना था कि वह पत्नी से रोज कहता था कि जिम मत जाया करो लेकिन वह मानती नहीं थी।

पुलिस के मुताबिक, कटघर क्षेत्र में डबल फाटक के पास टावर वाली गली निवासी शोभित गुप्ता की शादी दस साल पहले रामपुर जिले के बेलदारान निवासी पूनम गुप्ता के साथ हुई थी। दंपती की एक बेटी आराध्या भी है।

शोभित की डबल फाटक पर स्क्रैप की दुकान है। बताया जा रहा है कि पूनम गुप्ता एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाती थीं। शोभित इसका विरोध करता था। इसी बात को लेकर शोभित और पूनम के बीच अक्सर विवाद होता था। बुधवार की भी पूनम जिम गई थीं।

सुबह करीब दस बजे पूनम जिम से घर लौटीं तो पति से फिर विवाद हुआ। उस वक्त उनकी बेटी स्कूल जा चुकी थी। विवाद के बीच गुस्साए शोभित ने घर में रखे दुकान का शटर खोलने वाला हैंडल पत्नी के सिर पर मारकर हत्या कर दी।

इसके बाद पत्नी के शव को बेड पर रख दिया। शाम करीब छह बजे आरोपी ने एंबुलेंस को और 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर पत्नी के गिरकर घायल होने की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का शव बेड पर पड़ा था।

इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। सख्ती से की गई पूछताछ में उसने पुलिस के सामने हत्या की बात स्वीकार कर ली। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मायके वालों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

बेड पर पड़ा रहा शव, बचने की साजिश रचता रहा शोभित

शोभित ने अपनी पत्नी पूनम की हत्या को हादसा दिखाने और खुद को बचाने के लिए साजिश रची। दोपहर में स्कूल से आई बेटी ने अपनी मां के बारे में पूछताछ की तो शोभित ने उसे बताया कि वह बाहर गई है। शाम तक वापस आ जाएगी।

इसके बाद आरोपी ने बेटी को खाना खिलाया और दूसरे कमरे में सुला दिया। शाम को आरोपी ने पुलिस और एंबुलेंस को कॉल की। उसने बताया कि घर में काम करते समय उसकी पत्नी गिरकर घायल हो गई है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो महिला के सिर में चोट थी और उसकी मौत भी हो चुकी थी।

पूर्ति विभाग पर उठे गंभीर सवाल, संपत्ति जांच की उठी मांग

सुल्तानपुर। जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (च्वै) और घरेलू गैस आपूर्ति को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच पूर्ति विभाग एक बार फिर चर्चा में है। बहुजन अधिकार सेना (सामाजिक संगठन) के प्रदेश महासचिव शिवशंकर ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए जिला पूर्ति अधिकारी समेत सभी पूर्ति निरीक्षकों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राशन वितरण व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। पात्र लाभार्थियों को पूरा खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा, जबकि रिकॉर्ड में वितरण पूरा दिखाया जा रहा है। इसी तरह गैस वितरण में भी अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। संगठन का आरोप है कि विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं।

रोडवेज कर्मचारी संघ का गठन, सतीश चन्द्र मिश्रा बने अध्यक्ष

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की सुल्तानपुर डिपो शाखा का गठन आज विधिवत रूप से किया गया। चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी सतीश चन्द्र मिश्रा (क्षेत्रीय अध्यक्ष, अयोध्या क्षेत्र) एवं संजीव कुमार (शाखा मंत्री, अकबरपुर डिपो) की देखरेख में सम्पन्न हुई।

चुनाव के उपरांत सतीश चन्द्र मिश्रा को शाखा अध्यक्ष तथा प्रतीक श्रीवास्तव को शाखा मंत्री चुना गया। इसके साथ ही संगठन मंत्री पद पर देवेन्द्र मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष पद पर रामबदन को निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश चन्द्र मिश्रा ने की, जबकि संचालन बी०सी० शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शुक्ला (विभाग प्रमुख), दीपक मिश्रा (भारतीय मजदूर संघ) एवं राकेश शर्मा (जिला संयोजक) उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल द्वारा नामित सभासद मदन सोनकर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए परिचालक रेनू टण्डन को सर्वसम्मति से संगठन की आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया। इस अवसर पर बलिराम मिश्रा, कपिलदेव पाण्डेय, सुनील कुमार, तेजेन्द्र मिश्रा, अमर बहादुर मौर्या, जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, विवेक सिंह, विमलेश तिवारी, के०के० पाण्डेय, शेष नारायन पाण्डेय, श्रीनिवास पाण्डेय, संजीव प्रजापति सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ढैचा बीज संकट, किसान बेहद परेशान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले में कृषि व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दोस्तपुर, मोतिगरपुर समेत विभिन्न विकास खण्डों में संचालित राजकीय कृषि बीज भंडारों पर ढैचा बीज की अनुपलब्धता ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरित खाद के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली इस फसल के बीज समय पर न मिलने से किसानों की खेती की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें निजी बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है। जिले के कई बीज भंडारों पर पिछले कई वर्षों से ढैचा बीज की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वर्ष भी हालात में कोई विशेष सुधार नहीं दिख रहा है। किसान जब बीज लेने के लिए भंडारों पर पहुंचते हैं, तो उन्हें बार-बार यही जवाब मिलता है कि बीज अभी उपलब्ध नहीं है या कुछ दिनों बाद आएं। इस तरह की अनिश्चितता से किसानों का समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ढैचा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव फसल उत्पादन और मिट्टी के स्वास्थ्य दोनों पर पड़ेगा। इससे किसानों की आय प्रभावित होगी और कृषि लागत में भी अनावश्यक वृद्धि होगी। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। बीज भंडारों पर ढैचा बीज की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और भविष्य में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए ठोस योजना बनाई जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या व्यापक कृषि संकट का रूप ले सकती है।

हर 2 मिनट में एक टेक-ऑफ... जेवर एयरपोर्ट में अगले महीने से उड़ान शुरू, 17 शहरों के लिए होंगी सीधी फ्लाइट्स

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख लगने वाले हैं। देश के सबसे महत्वाकांक्षी एविएशन प्रोजेक्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से कमर्शियल उड़ानों के शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाल ही में संपन्न हुई यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) की बोर्ड बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगले माह यानी मई के अंत तक एयरपोर्ट से घरेलू और कार्गो विमानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट प्रशासन ने पहले चरण में 17 घरेलू रूटों पर उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि, शहरों की अंतिम सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र शामिल होंगे।

प्रबंधन ने इसके लिए तीन प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों के साथ शुरुआती दौर की वार्ता पूरी कर ली है। यात्रियों को किफायती सफर देने के लिए शुरुआत में लो-कॉस्ट करियर को प्राथमिकता दी जा रही है। घरेलू उड़ानों के सफल संचालन के बाद ही अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर विचार किया जाएगा।

हर 2 मिनट में उड़ान भरने की क्षमता

बोर्ड बैठक में एयरपोर्ट की क्षमता और विस्तार को लेकर कई अहम तकनीकी फैसले लिए गए। अगले दो सालों में विमानों की पार्किंग के लिए 25 नए स्टैंड बनाए जाएंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वर्तमान में 28 स्टैंड पूरी तरह तैयार हैं। जेवर एयरपोर्ट के रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि यहां से हर 2 मिनट में एक विमान टेक-ऑफ या लैंड कर सकेगा। यह क्षमता इसे दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की कतार में खड़ा करती है।

बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए आधुनिक लाउंज और प्रीमियम वेटिंग ज़ोन विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही, एयरपोर्ट परिसर के भीतर निर्माणाधीन भव्य होटल को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सुरक्षा मंजूरी और गृह मंत्रालय की क्लीयरेंस

हवाई सफर शुरू करने के लिए सबसे अनिवार्य एरोड्रम लाइसेंस और एएसपी (Aerodrome & ASP) सुरक्षा मंजूरियों पर काम तेज हो गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ। अरुण वीर सिंह के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई कुछ तकनीकी आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है। इसी महीने के भीतर सभी आवश्यक क्लीयरेंस मिलने की पूरी उम्मीद है, ताकि मई से बिना किसी बाधा के ऑपरेशन शुरू किया जा सके।

पश्चिमी यूपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा जेवर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक इंजन बनेगा। कार्गो उड़ानें शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ और आगरा के निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलेगी। इसके शुरू होने से लॉजिस्टिक, पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) का एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प बनेगा, जिससे हवाई यातायात का दबाव कम होगा। जेवर एयरपोर्ट का शुरू होना उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

गोरखपुर में 1,055 करोड़ रुपये की 497 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि इच्छाशक्ति हो तो अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। गोरखपुर नगर निगम ने महानगर के प्रवेश द्वार पर कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने का सराहनीय कार्य किया है। कई दशकों से पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बना एकला बंधा आज आधुनिक पर्यावरणीय उद्यान के रूप में विकसित होकर आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह केवल उद्यान ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो गया है, जहां लोग परिवार के साथ आकर भ्रमण और मनोरंजन कर सकते हैं। यह परिवर्तन गोरखपुर के दृढ़ संकल्प और सामूहिक कार्य का प्रतीक है। जब नीयत साफ होती है, तो परिस्थितियों को बदलने में देर नहीं लगती और यह बदलाव गोरखपुर के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है।मुख्यमंत्री गोरखपुर में राप्ती पर्यावरणीय उद्यान तथा नौसड़ से मलौनी मार्ग के लोकार्पण और लगभग 1,055 करोड़ रुपये की लागत से नगर निगम की 497 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया तथा अभियान के प्रचार सामग्री और उपकरण किट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया और राप्ती पर्यावरणीय उद्यान में पौधरोपण भी किया। इसके पश्चात 15वें वित्त आयोग और नगर निगम निधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नालों की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 31 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां गोरखपुर में परिवहन नगर बना है, वहां पहले शहर का कचरा डंप

किया जाता था, जो प्रदूषण का बड़ा कारण था। आज वहां उत्कृष्ट बाजार और मंडी स्थापित हो चुकी है। पहले एकला बंधे पर लगभग 2 लाख 26 हजार मीट्रिक टन कूड़ा जमा था, जिससे मीथेन गैस निकलती थी। इस कचरे का वैज्ञानिक विधि से उपचार कर सुरक्षित निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब वहां बच्चों के खेलने के लिए उद्यान विकसित हो गया है, जहां लोग योग और ध्यान भी कर सकते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर-वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए नौसड़ से मलौनी तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा चार लेन मार्ग बनाया गया है, जिससे नौसड़ क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या का समाधान हुआ है। इस मार्ग से लखनऊ, बांसगांव, बड़हलगंज और कौड़ीराम सहित अन्य स्थानों तक आवागमन सुगम हुआ है। पिछले नौ वर्षों में किए गए कार्यों के क्रम में गोरखपुर को उच्च स्तर की स्वच्छ नगरी बनाने तथा स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष तीन स्थानों में लाने के लक्ष्य के तहत स्कूली बच्चों के विशेष अभियान की शुरुआत की गई है।

उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण जैसी अवधारणाओं के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। पर्यावरणीय उद्यान में अपशिष्ट सामग्री से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कर प्रदर्शित किया गया है। प्रश्नोत्तरी और लघु वीडियो प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वच्छता का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है। गोरखपुर महानगर में एक लाख से अधिक बच्चे, दो हजार से अधिक शिक्षक, एक हजार से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी और अभिभावकों को इस अभियान से जोड़कर इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। उनके दृष्टिकोण के अनुरूप सभी नगर निगमों ने सुरक्षित और आधुनिक नगर के निर्माण की दिशा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। योजना के अंतर्गत आधुनिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। विभिन्न वार्डों में मार्गों का समुचित निर्माण, हरित पट्टी और लघु वन विकसित किए जा रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उद्यानों का सौंदर्यीकरण, मलिन बस्तियों का विकास तथा खुली नालियों को ढकने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में गोरखपुर में व्यापक बदलाव हुआ है। आज यहां बेहतर नालियां, ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। एकला बंधे पर प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, जो प्रदूषण रहित वातावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहां विकसित नगर वन पूरे क्षेत्र को हरियाली युक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से चिल्लूपार में होम्योपैथी महाविद्यालय का संचालन प्रारंभ हुआ है, जहां अनेक विद्यार्थी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले दक्षिणांचल क्षेत्र में बाढ़ की समस्या अधिक थी, लेकिन अब इसका काफी हद तक समाधान किया गया है। पहले गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, जबकि अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज तथा गोरखपुर एम्स में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। पहले लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता था, जबकि अब यहां चार विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लघु खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में उद्योगों की स्थापना हो रही है और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उर्वरक कारखाना संचालित हो चुका है तथा पिपराइच में चीनी मिल की स्थापना से क्षेत्र के विकास को गति मिली है। इन सभी परियोजनाओं का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि इनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके।कार्यक्रम के दौरान नगर निगम गोरखपुर के विकास कार्यों से संबंधित एक लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को सांसद रवि किशन शुक्ल, विधायक विपिन सिंह तथा गोरखपुर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जून तक चार लेन सड़क निर्माण पूरा करने के निर्देश, उपरिगामी सेतु कार्य में तेजी लाने पर जोर

गोरखपुर(आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में लगभग 379 करोड़ रुपये की लागत से बन रही राजघाट पुल से हरबत बंधा होते हुए डोमिनगढ़, माधोपुर बंधा, बसियाडीह मंदिर होते हुए महेसरा पुल तक निर्माणाधीन चार लेन सड़क तथा डोमिनगढ़ और जगतबेला के मध्य रेलवे लाइन पर 132 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन उपरिगामी सेतु का निरीक्षण किया।मुख्यमंत्री ने चार लेन सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाकर आगामी जून माह तक परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि महेसरा पुल के पास एकत्र कचरे का निस्तारण कर वहां पर्यावरणीय उद्यान की तर्ज पर उद्यान का निर्माण कराया जाए। साथ ही, महेसरा के पास स्थित तालाब की गाद निकासी कर उसकी मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किए जाने के निर्देश भी दिए। इन मार्गों का निर्माण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने डोमिनगढ़ पुलिस चौकी के पास डोमिनगढ़ और जगतबेला के मध्य रेलवे लाइन पर बन रहे उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों की भांति गोरखपुर में भी अनेक विकास कार्य संचालित हो रहे हैं। डोमिनगढ़ और जगतबेला के मध्य रेलवे लाइन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 755 मीटर तथा लागत 132 करोड़ रुपये है। सड़क और पुल के निर्माण से जंगल कौड़िया, घुनघुन कोठा सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लखनऊ, वाराणसी सहित अन्य शहरों में आवागमन में सुगमता होगी।इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

राजधानी के प्रसिद्ध वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. ए. के. त्रिपाठी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. ए. के. त्रिपाठी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट, लंदन में तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉ. त्रिपाठी ने अपने विभिन्न शोध कार्यों और शोधपत्रों को प्रस्तुत किया। उन्होंने वेट लॉस, पेट संबंधी रोग, किडनी डायलेसिस, पथरी, इनफर्टिलिटी, ऑटिज्म, त्वचा एवं मानसिक रोगों सहित कई जटिल बीमारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस दौरान नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों - इयोन मोर्गन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोनाथन ट्रॉट और डेविड गोवर की उपस्थिति में भी उन्हें सम्मानित किया गया।

बता दें कि डॉ त्रिपाठी को होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किये गए हैं। उन्होंने डॉ. हैनीमैन चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वे अब तक 3000 से अधिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किये हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को काफी लाभ मिला है।

नागरिक सुरक्षा प्रखंड लोहिया नगर की मासिक बैठक में बहादुर वार्डनों को किया गया सम्मानित

लखनऊ। नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केंद्र में प्रखंड लोहिया नगर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा ने सर्वप्रथम 15 अप्रैल 2026 को विकासनगर क्षेत्र में हुई आकस्मिक अग्निकांड दुर्घटना में अदम्य साहस और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य करने वाले वार्डनों की सराहना की। उन्होंने दुर्घटना के दौरान जनमानस की सहायता करते हुए घायल हुए पोस्ट वार्डन ऋषि श्रीवास्तव (पोस्ट वार्डन-3) को विशेष रूप से पुरस्कृत किया।अग्निकांड के समय विशेष सहयोग प्रदान करने वाले वरिष्ठ वार्डन अधिकारियों एवं कर्मियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। डिप्टी चीफ वार्डन गुरप्रीत सिंह सेठी, प आरक्षित पोस्ट वार्डन सौरभ अग्रवाल तथा सेक्टर वार्डन आमिर अब्बास सहित अन्य को लक्ष्मण पुरस्कार-2026 से नवाजा गया।

संक्षेप

30 अप्रैल तक सभी किसानों का पंजीकरण अनिवार्य, 15 मई से किसान पहचान संख्या होगी आवश्यक

लखनऊ। प्रदेश में जायद 2026 सीजन की तैयारियों के तहत सरकार ने किसानों के पंजीकरण अभियान को तेज कर दिया है। निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विशेष रूप से उन गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां अब तक पंजीकरण का स्तर कम है। अभियान के अंतर्गत सभी भूमिधर किसानों को शामिल किया जाएगा, चाहे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हों या नहीं।किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों को व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं कराने, स्थानीय समाचार पत्रों में सूचनाएं प्रकाशित कराने तथा ग्राम प्रधानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि प्रत्येक किसान तक समय पर जानकारी पहुंच सके और पंजीकरण कार्य में तेजी लाई जा सके।

30 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ होगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद का द्वितीय सत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्ष 2026 के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र को आहूत करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद-174 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद का द्वितीय सत्र गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे से विधान भवन स्थित परिषद मण्डप, लखनऊ में प्रारम्भ होगा। इस संबंध में राज्यपाल द्वारा 20 अप्रैल 2026 को आदेश जारी किया गया, जिसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि सत्र के आयोजन को लेकर आवश्यक सूचनाएं संबंधित सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रेषित कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा परिषद के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रति भेजी गई है, ताकि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्र में भाग ले सकें।इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सहित राज्यपाल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विधान परिषद के इस द्वितीय सत्र में विभिन्न शासकीय कार्यों, नीतिगत विषयों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।

इतिहास विभाग के प्रो. एस. विक्टर बाबू 45वें वार्षिक अधिवेशन के महाध्यक्ष नामित

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्य अधिष्ठाता पद पर कार्यरत प्रो. एस. विक्टर बाबू को साउथ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 45वें वार्षिक अधिवेशन का महाध्यक्ष नामित किया गया है। प्रो. विक्टर बाबू का यह नामांकन उनके लंबे समय से चले आ रहे शोध कार्य, विद्वता और शैक्षणिक नेतृत्व का सम्मान है, जो इतिहास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान और विशिष्ट पहचान को दर्शाता है।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने प्रो. एस. विक्टर बाबू को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनकी इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया।यह अधिवेशन जुलाई 2026 में तेलंगाना राज्य के नलगोंडा स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के विद्वानों की सहभागिता अपेक्षित है। प्रो. विक्टर बाबू के मार्गदर्शन में आयोजित यह अधिवेशन इतिहास के क्षेत्र में नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।उल्लेखनीय है कि साउथ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। यह संगठन दक्षिण भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज से जुड़े शोध एवं विमर्श को बढ़ावा देने वाला एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंच है।

नीम के पेड़ से फांसी लगाकर व्यक्ति ने की आत्महत्या, दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम बहरु में एक व्यक्ति द्वारा नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को थाना काकोरी में साधना पुत्री स्वर्गीय सालिकराम, निवासी ग्राम बहरु, थाना काकोरी, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि उनके पति रामबालक सैनी पुत्र मुन्नू, उम्र लगभग 44 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की।प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक रामबालक सैनी, निवासी ग्राम गौरा थाना आसीवन, जनपद उन्नाव, पिछले लगभग 14 वर्षों से अपनी ससुराल ग्राम बहरु, थाना काकोरी, लखनऊ में रह रहा था। बताया गया कि उसने गांव के निकट स्थित एक नीम के पेड़ पर बिजली के केबल का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और परिजनों में चीख-पुकार मच गई।मृतक अपने पीछे दो छोटे पुत्रों को छोड़ गया है, जिनकी उम्र लगभग 5 वर्ष और 7 वर्ष बताई जा रही है। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया।

नगर निगम के विशेष सदन में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा, 93 पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव किया पारित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ में गुरुवार को आयोजित विशेष सदन में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में प्रातः 11 बजे प्रारम्भ हुई इस बैठक में पार्षदों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति रही। सदन के दौरान हालिया घटनाक्रम तथा महिला सम्मान से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता के साथ विचार-विमर्श किया गया।सदन को संबोधित करते हुए लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने भावुक शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह केवल महापौर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सैनिक परिवार से जुड़ी महिला के रूप में भी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अनुशासन और स्वाभिमान उनके जीवन के मूल मूल्य रहे हैं, लेकिन

बुधवार की सुबह उनके आवास पर हुई घटना ने लोकतंत्र और मानवता दोनों को आहत किया है।सदन के दौरान कई पार्षदों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पार्षद रेखा सिंह, नेहा सिंह, शिवम उपाध्याय, गौरी सांवरिया, ऋचा मिश्रा, भृगुनाथ शुक्ला तथा अनुराग मिश्रा (अन्नू) ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में बोलते हुए महिला सशक्तिकरण, समान अधिकार और सामाजिक सम्मान की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिलना समय की आवश्यकता है।महापौर ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस देश में नदियों को 'मां' कहा जाता है, वहां नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मां, बहन और बेटी जैसे पवित्र रिश्तों का अपमान देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक मां होने के नाते वह किसी भी मां का अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकतीं।उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया तथा महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विरोध कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि अब देश की नारी जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है।महापौर ने बुधवार को उनके आवास पर हुए प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी नामपट्टिका पर जूता चलाना न केवल उनके पद का, बल्कि पूरे शहर की गरिमा का अपमान है। उन्होंने इसे लखनऊ की प्रथम नागरिक तथा एक सैनिक परिवार की महिला के सम्मान पर आघात बताया।सदन में इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 119 में से 93 पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया।

ऋण दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने वाला वांछित अभियुक्त मेरठ से गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। ऋण दिलाने के नाम पर आम जनता से धन एकत्र कर हड़पने के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त मो. फराज उर्फ सनी राणा को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने जनपद मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त की तलाश के क्रम में की गई। गिरफ्तार अभियुक्त कंपनी में निदेशक पद पर कार्यरत था और लोगों से धन एकत्र कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है।प्रकरण के अनुसार, शताब्दी फिन कार्प प्रा. लि. कंपनी के संचालक, निदेशकगण एवं खाताधारकों द्वारा आम जनता को बैंकों से गृह ऋण, शिक्षा ऋण, कृषि ऋण तथा आयकर विवरणी के आधार पर ऋण दिलाने का झांसा दिया जाता था। इसके लिए आवेदकों से कंपनी के बैंक खातों में फाइल शुल्क, प्रक्रिया शुल्क तथा सेवा कर के नाम पर धन जमा कराया जाता था। आरोप है कि कंपनी द्वारा आवेदकों को ऋण स्वीकृत कराने के बजाय उनसे जमा कराए गए कुल 3,91,783 रुपये हड़प लिए गए और बाद में कंपनी का कार्यालय बंद कर आरोपी फरार हो गए। इस प्रकार कई लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया।इस संबंध में आर्थिक अपराध शाखा सेक्टर मेरठ थाना में मुकदमा संख्या 32/19 के तहत धारा 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (1) ए के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में कुल चार अभियुक्तों की संलिप्तता सामने आई, जिन्हें दोषी पाया गया। इनमें से एक वांछित अभियुक्त मो. फराज उर्फ सनी राणा को 23 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न में जनपद मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया।जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत था और लोगों को ऋण दिलाने के नाम पर धन जमा कराने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे शेष फरार अभियुक्तों तक पहुंचने में मदद मिल सके।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मो. फराज उर्फ सनी राणा पुत्र मो. हसन, निवासी 112 विकास पुरी कालोनी, जनपद मेरठ के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई इस गिरफ्तारी को मामले में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। पुलिस द्वारा शेष तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

स्कूल की छत से गिरकर मजदूर की मौत, काम के दौरान हुआ हादसा

लखनऊ। इटौंजा क्षेत्र के सिरसा कमालपुर स्थित एक स्कूल में शेड निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की छत से गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल अवस्था में मजदूर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि सिरसा कमालपुर, इटौंजा, लखनऊ स्थित एक स्कूल में ठेकेदार आदिल सिद्दीकी निवासी अचरामऊ, थाना बीकेटी, लखनऊ द्वारा शेड निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। ठेकेदार पहले भी उक्त स्कूल में इसी प्रकार के निर्माण कार्य की देखरेख कर चुका था। निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को मजदूरी के लिए लेकर आया था, जो स्कूल की छत पर कार्य कर रहा था।

महापौर ने विपक्ष पर साधा निशाना, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर 93 पार्षदों का जताया आभार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी की महापौर ने अपने आवास पर हुई घटना को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह यहां केवल लखनऊ की महापौर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सैनिक परिवार की सदस्य के रूप में भी खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वह एक सैनिक की बेटी, बहन, बहू और पत्नी रही हैं तथा पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में अनुशासन और स्वाभिमान के मूल्यों को आत्मसात किया है। उन्होंने कहा कि बुधवार की सुबह उनके आवास पर जो घटना हुई, उसने लोकतंत्र और मानवता दोनों को शर्मसार कर दिया है।महापौर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश में हम रहते हैं, उसे भारत माता कहा जाता है और यहां

नदियों को भी मां का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं से जुड़े पवित्र रिश्तों—मां, बहन और बेटी—का अपमान करने की घटना को देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह स्वयं एक मां हैं और उनके लिए देश की हर जननी शक्ति का स्वरूप है, ऐसे में किसी मां का अपमान करना उनके संस्कारों के विपरीत है।उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने वर्षों तक देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित रखा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कानूनों का विरोध किया। महापौर ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर अब देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और किसी भी अपमान का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा।महापौर ने आरोप लगाया कि बुधवार सुबह विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवास पर पहुंचकर नामपट्टिका पर जूते चलाना न केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि यह शहर की प्रथम नागरिक और एक सैनिक की पत्नी का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक की पत्नी होने के नाते उन्होंने चुनौतियों का सामना करना सीखा है और वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा दृढ़ रहेंगी।इस प्रकरण के बीच नगर निगम में 119 में से 93 पार्षदों द्वारा एकजुट होकर निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए जाने पर महापौर ने सभी पार्षदों और शहर की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केवल औपचारिक कार्यवाही नहीं, बल्कि उन लोगों को जवाब है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान का उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ की तहजीब और न्यायप्रियता आज भी जीवित है और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

बस्तर के लिए खुले वैश्विक द्वार, 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर

बस्तर की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (एनएच-130 सीडी) एक क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान कर लैंड-लॉक्ड क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करेगा। वर्तमान में जगदलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के कठिन घाटों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 से 9 घंटे का समय लगता है। भारी वाहनों के लिए यह मार्ग न केवल थकाऊ है, बल्कि डीजल की खपत और मेंटेनेंस के लिहाज से भी खर्चीला है। नया कॉरिडोर इस यात्रा को मात्र 3.5 से 4 घंटे में समेट देगा। सीधा और घाट-मुक्त रास्ता होने के कारण वाहनों का परिचालन खर्च काफी कम हो जाएगा, जिससे परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (एनएच-130 सीडी) छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर और कोंडागांव जिलों से गुजर रहा है। जगदलपुर मुख्यालय को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए ओडिशा के नबरंगपुर का दासपुर इंटरचेंज महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। जगदलपुर का ट्रैफिक मात्र 50-60 किमी का सफर तय कर नबरंगपुर इंटरचेंज के माध्यम से रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो सकेगा, जिससे बस्तर सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ जाएगा।

इस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बस्तर की अरेबिका कॉफी, जैविक इमली, महुआ उत्पाद और प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुँचाना सुगम होगा। कम लॉजिस्टिक लागत के कारण ये उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय किसानों, संग्रहकर्ताओं और शिल्पकारों को उनकी उपज का बेहतर अंतरराष्ट्रीय मूल्य मिल सकेगा।

बस्तर, कांकेर और कोंडागांव जैसे आकांक्षी जिलों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं इन सुदूर क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी। इस राजमार्ग के माध्यम से बस्तर का कृषि उत्पाद और इस्पात सीधे रायपुर, दुर्ग-भिलाई और विशाखापट्टनम जैसे औद्योगिक केंद्रों से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी, प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर में हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह कॉरिडोर बस्तर में औद्योगिक विकास की एक नई लहर लाने के लिए तैयार है। बस्तर क्षेत्र लौह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। यह कॉरिडोर इन खनिजों को विशाखापत्तनम पोर्ट तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे निर्यात और व्यापार में भारी उछाल आएगा। कॉरिडोर के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

कनेक्टिविटी में सुधार होने से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकल गणेश, कुतुमसर गुफा और चित्रकोट-तीरथगढ़ जैसे जलप्रपातों तक पहुंच आसान होगी। इससे न केवल पर्यटन राजस्व बढ़ेगा, बल्कि आदिम संस्कृति और लोक कलाओं को भी वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी।

कांकेर जिले के बासनवाही के मंझिनगढ़ पहाड़ी (केशकाल) को चीरकर 2.79 किमी लंबी छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन-ट्यूब टनल बनाई जा रही है। यह टनल उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव जोन से गुजरती है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वन्यजीवों का आवागमन बाधित न हो। साथ ही पूरे राजमार्ग में मंकी कैनोपी, एनिमल अंडरपास और ओवरपास बनाए जा रहे हैं ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (एनएच-130 सीडी) बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लगभग 16,491 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह 464 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर न केवल दूरी कम करेगा, बल्कि बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सेतु का काम करेगा। यह कॉरिडोर बस्तर को विश्व व्यापार की मुख्यधारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह परियोजना सही मायने में बस्तर की आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान का आधार बनेगी।

पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर का फायदा क्या उठा पाएगी भाजपा?

मतदाताओं के एक हिस्से में यह धारणा भी है कि भाजपा की राजनीति अत्यधिक ध्रुवीकरण पर आधारित है।

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सवाल सीधा है कि क्या सत्ताविरोधी माहौल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने पक्ष में मोड़ पाएगी? या फिर ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर कायम रहेगा? वैसे राज्य में चुनावी हवा भले ही बदलाव की सुगबुगाहट दिखा रही हो, लेकिन जमीन पर हालात इतने सरल नहीं हैं। देखा जाये तो इस बार के चुनावों में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां, केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और संगठन की आक्रामक रणनीति यह संकेत देती है कि पार्टी किसी भी कीमत पर बंगाल में सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी अपनी पकड़ ढीली पड़ने देने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी, जो लंबे समय से राज्य की राजनीति का केंद्र रही हैं, अब भी अपने जनाधार और कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे मैदान में डटी हुई हैं।

उधर, भाजपा के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है 'एंटी-इंकम्बेंसी' यानी सत्ता के खिलाफ बढ़ती नाराज़गी। टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और कानून-व्यवस्था के सवालों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। भर्ती घोटाले, स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की दबंगई और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे भाजपा के चुनावी एजेंडे के केंद्र में हैं। पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार वोट उसी दिशा में जाएगा।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। ममता बनर्जी ने बीते वर्षों में महिला मतदाताओं, ग्रामीण गरीबों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया है, जबकि अन्य सामाजिक योजनाओं ने गरीब तबकों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यही कारण है कि भाजपा के आक्रामक अभियान के बावजूद टीएमसी का आधार पूरी तरह हिलता नजर नहीं आता।

इसके अलावा, भाजपा की रणनीति में एक अहम किरदार हैं शुभेन्दु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे और अब उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं। शुभेन्दु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी और इस बार ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं। शुभेन्दु अधिकारी राज्य में भाजपा का चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि, उनका प्रभाव सीमित इलाकों तक ही केंद्रित माना जाता है, और पूरे बंगाल में एक व्यापक लहर खड़ी करना उनके लिए आसान नहीं है।

हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में टर्निंग प्वाइंट साबित हुए थे। पार्टी ने उस चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल करते हुए खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। उसी प्रदर्शन के आधार पर भाजपा को उम्मीद थी कि वह विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंच सकती है। लेकिन बाद के चुनावी अनुभवों ने यह भी दिखाया कि लोकसभा और विधानसभा की राजनीति में मतदाताओं का व्यवहार अलग हो सकता है।

एक और चुनौती भाजपा के सामने सांस्कृतिक और भाषाई असंतुलन की है। बंगाल की अपनी विशिष्ट पहचान है, और यहां बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा अक्सर उभरता रहता है। भाजपा के कई नेताओं के बयान और रणनीतियां कभी-कभी स्थानीय संवेदनशीलताओं से मेल नहीं खातीं, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। टीएमसी इस मुद्दे को भुनाने में माहिर रही है और खुद को 'बंगाल की असली आवाज' के रूप में पेश करती है।

इसके अलावा, मतदाताओं के एक हिस्से में यह धारणा भी है कि भाजपा की राजनीति अत्यधिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। धार्मिक और पहचान की राजनीति का असर भले कुछ क्षेत्रों में दिखता हो, लेकिन पूरे राज्य में यह रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर सवाल बना हुआ है। बंगाल का सामाजिक ताना-बाना जटिल है, और यहां की राजनीति सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं टिकती।

दूसरी ओर, टीएमसी के खिलाफ असंतोष को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ग्रामीण इलाकों में विकास की असमानता, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दे लोगों के बीच चर्चा में हैं। भाजपा इन्हीं सवालों को उठाकर खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है।

वैसे बंगाल की चुनावी लड़ाई सिर्फ आंकड़ों और नारों की नहीं है, बल्कि भावनाओं, पहचान और भरोसे की भी है। भाजपा के पास आक्रामक अभियान और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन है, लेकिन टीएमसी के पास जमीनी नेटवर्क और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है। इसलिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि सत्ताविरोधी लहर किसके पक्ष में जाएगी। भाजपा के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी क्योंकि उसे नाराज़गी को वोट में बदलना होगा। वहीं ममता बनर्जी के लिए यह अपनी विश्वसनीयता और जनसंपर्क की सबसे बड़ी परीक्षा है। बहरहाल, इस चुनाव का नतीजा सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता में पुनरावृत्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि बंगाल की राजनीति आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल, मैदान सजा है, दांव बड़े हैं और फैसला पूरी तरह जनता के हाथ में है, जो इस बार सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि राजनीतिक कथा का अगला अध्याय लिखने जा रही है।

टिप्पणी

प्रगति का लंबा रास्ता

साल 1990 में भारत में औसतन हर एक लाख शिशु जन्म के दौरान 508 माताओं की मौत होती थी। ये संख्या 2023 में 116 तक आ गिरी। फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर कम विकसित देशों की श्रेणी में ही आता है।

मातृत्व मृत्यु दर की अवस्था (शिशु को जन्म देने के क्रम में माताओं की होने वाली मौतें) सामाजिक विकास का एक प्रमुख पैमाना है। बीते साढ़े तीन दशक में भारत ने इस कसौटी पर अच्छी प्रगति की है। लेकिन 2015 के बाद से प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। मशहूर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लांसेट ने एक ताजा अध्ययन रिपोर्ट में बताया है कि साल से 2000 से 2015 की अवधि सबसे तेज प्रगति की रही, जब अस्पताल/ क्लीनिक में प्रसव, प्रसव-पूर्व देखभाल में सुधार, और आम तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के कारण मातृत्व मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई। लेकिन 2015 से 2023 की अवधि में ये रफ्तार सुस्त हो गई है।

अध्ययनकर्ताओं ने कहा है कि ये परिघटना उन व्यवस्थागत चुनौतियों की ओर इशारा करती है, जिनका हल ढूंढना कठिन बना हुआ है। प्रसव के दौरान अधिक खून बहना, हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें, और आम देखभाल में कमी गर्भावस्था या डिलिवरी के दौरान माताओं की मौत की बड़ी वजहें बनी हुई हैं। ये वो कारण हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है, मगर उसके लिए लक्ष्य केंद्रित सार्वजनिक पहल की जरूरत है। संभवतः इसमें कमी के कारण ही 2023 में भारत में 24,700 महिलाओं की मौत मां बनने के क्रम में हो गई। 1990 में ये संख्या 1.19 लाख और 2015 में 36,900 थी। जाहिर है, प्रगति का क्रम बना हुआ है, मगर वार्षिक प्रगति की रफ्तार धीमी हुई है।

1990 में भारत में औसतन हर एक लाख शिशु जन्म के क्रम में 508 माताओं की मौत होती थी। ये संख्या 2023 में 116 तक आ गिरी। इसके बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दर के साथ भारत वैश्विक स्तर पर नाईजीरिया, इथोपिया और पाकिस्तान जैसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत प्रति एक लाख जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर को 70 के नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत को अभी भी प्रगति का लंबा रास्ता तय करना है। अतः जरूरी है कि इसकी रफ्तार धीमी ना होने दी जाए।

ब्लॉग

महिला कोटे से जुड़े संविधान बिल के लुढ़कने के सियासी निहितार्थ

कमलेश पांडे

इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकजुटता ने पुनः सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से जुड़ा था, 16 अप्रैल 2026 को वोटिंग में गिर गया। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत (लगभग 352 वोट) की आवश्यकता थी, जो सरकार के रणनीतिकारों ने नहीं जुटा पाए। शायद पहली बार सदन में अमित शाह की रणनीति पिट गई। इसका राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि मोदी सरकार के लिए 12 साल में पहली बड़ी संवैधानिक हार हुई है, जो विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे 'संविधान पर हमला' बताकर कांग्रेस-विपक्ष की रणनीति की जीत घोषित की, जबकि भाजपा इसे विपक्ष विरोधी हथियार बनाने की योजना बना रही है। एक सत्ता विरोधी रणनीति के तहत जहां विपक्ष ने बिल को 'छलावा' करार दिया, वहीं दावा किया कि यह परिसीमन और चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। वहीं, एक एनडीए नेता के अनुसार, बिल गिरने से सरकार अब सड़क पर विपक्ष को महिलाओं के अधिकारों के नाम पर घेरेगी।

हालांकि, सरकार ने शेष दो बिल (परिसीमन और अन्य) आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि वे मुख्य बिल पर निर्भर थे। एचएम अमित शाह और पीएम मोदी विपक्ष के विरोध को कांग्रेस के इतिहास से जोड़कर जनता में प्रचार करेंगे। यह 2029 चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज कर सकता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में भी दिख सकता है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का पुनः संदेश गया है। वहीं, मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने के लिए रणनीतिक बदलाव कर सकती है, खासकर 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हार के बाद। समझा जाता है कि सरकार नई विधेयक रणनीति के तहत दो या तीन नए विधेयक ला सकती हैः पहला लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करेगा, जिसमें एससी/एसटी के लिए सब-कोटा भी शामिल होगा। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं? दूसरा परिसीमन आयोग स्थापित करेगा, लेकिन इसे राज्यों के अनुमोदन से अलग रखा जा सकता है ताकि दो-तिहाई बहुमत आसान हो।

सरकार का मानना है कि विपक्ष से सहमति निर्माण के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी सभी दलों को पत्र लिखकर सर्वसम्मति की अपील कर चुके हैं, इसी सिलसिले में कांग्रेस और अन्य विपक्षियों से बातचीत जारी है। महिला कोटा बिल को 2029 चुनावों से पहले लागू करने के लिए 2011 जनगणना पर आधारित संशोधन पर जोर दिया, और नई जनगणना-परीक्षण का इंतजार खत्म किया जाएगा। इसके निमित्त संसदीय प्रक्रिया यह हैं कि विशेष सत्र बुलाकर संशोधित बिल पेश करना संभव होगा, जहां 18 घंटे लोकसभा और 10 घंटे राज्यसभा चर्चा होगी। वहीं सड़क पर प्रचार के साथ विपक्ष को ओबीसी हितों पर घेराव, जिससे राजनीतिक दबाव बनेगा। यह 2029 से पहले बहुमत जुटाने की कोशिश होगी। इस प्रकार देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को 2029 से पहले लागू करना संवैधानिक रूप से जटिल है, क्योंकि इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया अनिवार्य है जो 2011 जनगणना पर आधारित होनी चाहिए। इसका संभावित विकल्प संशोधित बिल पुनर्प्रस्तावहै जिसके तहत सरकार दोबारा संशोधित विधेयक ला सकती है, जिसमें लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला कोटा सुनिश्चित हो, लेकिन विपक्ष सहमति के बिना दो-तिहाई बहुमत मुश्किल है। इसलिए विपक्ष से सर्वसम्मति की पहल तेज है। सरकार सभी दलों से बातचीत तेज कर विशेष सत्र बुलाना, परिसीमन को अलग रखकर बिल पास करवाना, हालांकि विपक्ष इसे 'परिसीमन साजिश' मान रहा है।

जहाँ तक व्यावहारिक बाधाओं की बात है तो परिसीमन आयोग को पब्लिक हियरिंग और प्रक्रिया में कम से कम 2-3 वर्ष लगते हैं, इसलिए 2029 चुनाव से पहले पूरा होना असंभव है। वहीं बिल गिरने से अब अगली जनगणना (2031) और उसके बाद के परिसीमन तक (2034+) देरी तय, दक्षिणी राज्यों की चिंताएं टल सकती हैं। सरकार सड़क प्रचार पर जोर देगी। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर मुख्य रूप से परिसीमन प्रक्रिया, ओबीसी/एससी/एसटी सब-कोटा और राजनीतिक साजिश को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित हैंः-

पहला, परिसीमन साजिशः बिल को लोकसभा/विधानसभा सीटें बढ़ाने और 2011 जनगणना पर परिसीमन से जोड़ा गया, जिसे विपक्ष ने उत्तर भारत (विशेषकर भाजपा शासित राज्यों) को लाभ पहुंचाने वाली 'सीट रिबनिंग' करार दिया। फलतः दक्षिणी राज्य अपनी सीटें खोने के डर से विरोधी हो गए।

दूसरा, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुपस्थितिः 33% महिला कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब-कोटा न होने से सामाजिक न्याय का उल्लंघन ठहराया, और इसे 'सवर्ण महिलाओं के लिए' नया मौका बताया।

तीसरा, संविधान पर हमलाः राहुल गांधी ने इसे 'संविधान बचाओ' का मुद्दा बनाया, और दावा किया कि बिल चुनावी नक्शा बदलकर विपक्ष कमजोर करेगा। इस प्रकार राजनीतिक तर्क देते हुए विपक्ष ने इसे 'छलावा' कहा, क्योंकि लागू होने में 2029-34 तक देरी होगी। इसलिए एकजुट होकर वोटिंग में भाजपा नीत एनडीए को हराया। वहीं, मोदी सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया, जो 25-30 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। परिसीमन पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि परिसीमन 2011 जनगणना पर आधारित होगा, जो निष्पक्ष है और दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा; यह सीट वृद्धि के साथ संतुलित होगा। अमित शाह ने चुनौती दी कि यदि विपक्ष संशोधन चाहे तो सदन एक घंटा रोकें, वे तुरंत बदलाव लाएंगे। वहीं, ओबीसी/एससी/एसटी कोटा पर जवाब देते हुए सरकार ने ओबीसी/ईडब्ल्यूएस सब-कोटा की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने स्पष्ट कहा कि संविधान धर्म या जाति आधारित अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति नहीं देता; इसलिए मौजूदा एससी/एसटी कोटा में महिलाओं को प्राथमिकता रहेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष को 'महिलाओं के खिलाफ' करार दिया, और कहा कि पंचायत स्तर पर सफलता साबित हो चुकी है।

कहानी तोता-मैना मजार की... एक पक्षी ने लिया 'बदला', बादशाह को बताया हर कातिल का नाम

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित तोता-मैना पुल और उनकी मजार आज भी प्रेम, वफादारी और त्याग की एक अनोखी कहानी को जीवित रखे हुए है। अयोध्या से जुड़े इस ऐतिहासिक जिले में कई धार्मिक और रहस्यमयी स्थल मौजूद हैं, जिनमें सतरिख थाना क्षेत्र के सेराय अकबराबाद गांव का यह स्थल अपनी खास पहचान रखता है।

कहा जाता है कि यह पुल मुगल काल में बनवाया गया था और इसके साथ जुड़ी कहानी बेहद दिलचस्प और भावुक है। लोक कथाओं के अनुसार, एक मुगल बादशाह के वजीर का काफिला इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी बदमाशों ने हमला कर उन्हें लूट लिया और वजीर की हत्या कर दी। वजीर के साथ पिंजरे में एक तोता और मैना भी थे, जो इंसानों की तरह बोलते थे।

हमले के दौरान तोते ने बदमाशों को चेतावनी दी कि वह उनकी पहचान बता देगा, जिससे गुस्साए हमलावरों ने उसे मार डाला। वहीं मैना ने चतुराई दिखाते हुए खुद को मृत होने का नाटक किया। बदमाशों के जाने के बाद वह उनके पीछे-पीछे गई और बाद में दिल्ली पहुंचकर बादशाह को पूरी घटना बताई। मैना की गवाही के आधार पर सभी अपराधियों को पकड़कर सजा दी गई।

क्या है तोता-मैन पुल की कहानी?

बताया जाता है कि इसके बाद बादशाह ने उस स्थान पर, जहां वजीर और तोते की मौत हुई थी, उन्हें दफनाने का आदेश दिया। मैना ने भी अपने साथी के साथ दफन होने की इच्छा जताई, जिसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। दोनों की याद में वहां मजार बनवाई गई और पास बहने वाले नाले पर एक मजबूत पुल का निर्माण कराया गया, जिसे आज तोता-मैना पुल के नाम से जाना जाता है।

हर साल लगता है यहां मेला

यह स्थल न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि हर साल यहां लगने वाला मेला भी आस्था और आकर्षण का केंद्र बनता है। दूर-दराज से हजारों श्रद्धालु यहां आकर मजार पर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की मन्नत मांगते हैं। सदियों पुरानी यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और तोता-मैना पुल को प्रेम और वफादारी की अनोखी मिसाल बनाती है।

मुरादाबाद में डबल मर्डर! बेटी ने मां–भाई को रॉड से वार कर मार डाला, गांव में भारी पुलिसबल तैनात

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कांठ क्षेत्र के भैंसिया जमालपुर गांव में एक युवती ने अपनी ही मां और भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में भय और सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

पुलिस के अनुसार, घटना शाम के समय हुई, जब घर के भीतर किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने अपना आपा खो दिया और हिंसक हो उठी। गुस्से में आकर उसने घर में रखी लोहे की सरिया उठाई और अपनी मां व भाई पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घर का दृश्य बेहद भयावह था। मां और बेटे के शव खून से लथपथ पड़े थे, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। जैसे ही इस वारदात की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना कांठ पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का बारीकी से जायजा लिया और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवती मानसिक रूप से अस्थिर बताई जा रही है, जिसके चलते उसने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या के पीछे सिर्फ मानसिक स्थिति ही कारण थी या कोई अन्य विवाद भी शामिल था।

इस मामले में मृतका के बड़े बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी युवती को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

इस संबंध में एसपीकुंवर आकाश सिंह ने बताया कि शाम करीब 7 बजे मां-बेटे की हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि दोनों अपने घर में मृत पड़े थे। उन्होंने बताया कि आरोपी बेटी मानसिक रूप से कुछ असंतुलित है और कहासुनी के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक ही परिवार के दो सदस्यों की हत्या और वह भी घर की बेटी द्वारा किए जाने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

सपा में शामिल होने का विरोध करने वालों को बताया अदूरदर्शी अंधभक्त

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। मोस्ट निदेशक शिक्षक श्यामलाल निषाद "गुरूजी" ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के अपने निर्णय का औचित्य स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य देश की संप्रभुता की रक्षा करना और संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र कराना है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता, लोकतंत्र की जो परिभाषा चुनाव आयोग की जो विशेषता, संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिबद्धता का जो पाठ हम बच्चों को क्लास रूम में पढ़ाते हैं वह वास्तव में देश के अंदर यथार्थ में दिखाई नहीं देता, हम संविधान में दिए गए अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जो बातें बच्चों को क्लास रूम में पढ़ाते हैं समाज में वह नहीं दिखती। देश के संसाधनों और सत्ता न्याय पूर्ण भागीदारी आज भी नहीं दिख रही है हम चाहते हैं कि जो संविधान में है वैसा समाज में भी होना चाहिए, इसी

आशा और विश्वास से हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। देश भारत के संविधान में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की गारंटी दी गई है लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद होने से बचाने के लिए हम मोस्ट के लोगो ने सरकार के गलत निर्णय के विरोध में विभिन्न जनपदों में भीषण प्रदर्शन भी किए किंतु मौजूदा सरकार संवैधानिक गारंटी के अनुकरण में पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती, ग्रामीणों/पिछड़ों के बच्चों की शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि करने के बजाय स्कूल बंद कर रही है। आज अमीर लोग यह कह कर कि गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है अपने बच्चों को शहर भेज दे रहे हैं किंतु जो साधन संपन्न नहीं है ऐसे गरीब/पिछड़ों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी मिलना मुश्किल हो रही है योगी सरकार को इतना भी ज्ञान नहीं कि राष्ट्र का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है इसी लिए हम मोस्ट के लोग प्रदेश में खास करके पूर्वांचल में निःशुल्क मोस्ट पाठशालाएं चलवाने का काम कर रहे हैं हमें उम्मीद है कि समाजवादी सत्ता में आने के बाद प्रदेश की बर्बाद की जा रही प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। श्यामलाल निषाद ने कहा कि बीजेपी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता का खत्म कर रही है देश की संप्रभुता अमेरिका के हाथों सौंप चुकी है! ऐसा लगता है कि देश भारत आज अमेरिका का उपनिवेश बनकर रह गया है, देश के संसाधनों और संपत्ति अपने चहेते चंद पूंजीपतियों के हवाले करते चले जा रहे हैं। मोस्ट निदेशक ने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ में अंधविश्वास, पाखंडवाद, जाति श्रेष्ठ को बढ़ावा देकर देश की एकता और अखंडता भाई चारा को कमजोर कर रही है और जो उसके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एफआईआर, निलंबन आदि का डर दिखाकर आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है जिसका मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूं।

अपमान की 'खौफनाक सजा' खुद को दी, आग लगाकर हिमांशु ने किया सुसाइड, गांव में भारी पुलिसबल तैनात

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। बागपत जिले के गंगधाड़ी गांव में तनाव का माहौल है। गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। थप्पड़ मारने और जातिसूचक शब्द कहे जाने से आहत युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। बीते मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे गांव में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है।

जानकारी के अनुसार बीते 17 अप्रैल को मृतक 22 वर्षीय हिमांशु और गांव के ही टिंकू उर्फ गौरव राजपूत के बीच गाड़ी में फूल लदवाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि हिमांशु ने गाड़ी में फूल लादने से मना कर दिया था, जिसके बाद गौरव ने उसे जातिसूचक शब्द कहे और थप्पड़ भी मारे।

इससे आहत होकर रात करीब 9 बजे उसने गौरव के घर के पास

पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। इससे वह पूरी तरह झुलस गया और उसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शव पहुंचते ही गांव में तनाव

बुधवार जैसे ही शव गांव पहुंचा तनावर की स्थिति पैदा हो गई। परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। मौके पर मौजूद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन माने और शव का अंतिम संस्कार किया गया।

गिरफ्तार हो चुका है आरोपी

घटना के अगले दिन 18 अप्रैल को परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टिंकू को गिरफ्तार किया था और उसका चालान कर दिया था। घटना से जुड़ा एक सीवीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रात करीब 9: 30 बजे मृतक टिंकू के घर के पास खुद को आग लगाते हुए दिख रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जान से मारने की धमकी पांच के खिलाफ रिपोर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निशान उदियासन नहर के पास एक महिला के इकलौते बेटे को जान से मारने की नीयत से घेरने और पुराने मुकदमे में सुलह न करने पर हत्या की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ति की तहरीर पर पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निशान गांव निवासी जमीला पत्नी रशीद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके पड़ोसी सनवर, मेंहदीहसन उर्फ मोनू, सद्दाम, चांद मोहम्मद पुत्रगण मुद्दी और सोहराब पुत्र रुस्तम काफी दबंग और सरकस किस्म के व्यक्ति हैं । पीड़ति के अनुसार, इन लोगों ने पहले भी उनके घर में घुसकर उनके और बच्चों के साथ मारपीट की थी, जिसके संबंध में बीते मार्च माह में थाना गौराबादशाहपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि उसी रंजिश को लेकर बीते शनिवार सुबह करीब 8 बजे जब पीड़ति का इकलौता बेटा सन्नी उदियासन नहर के पास था, तो उपरोक्त आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से घेर लिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह अपनी मां के पास पहुंचा। पीड़ति का कहना है कि आरोपी लगातार उन पर पुराने मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यदि सुलह नहीं की तो उनके बेटे को जान से मार देंगे और उनकी संपत्ति छीन लेंगे। आरोपियों ने तहरीर देने पर उनकी बेटी के साथ भी अनहोनी की धमकी दी है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव के निर्देश पर पुलिस ने सनवर, मेंहदीहसन, सद्दाम, चांद मोहम्मद और सोहराब के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मुन्ना लाल शर्मा को सौंपी गई है।

ट्रक से 400 लीटर डीजल चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात

सुल्तानपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के ओदरा गांव में बाईपास किनारे खड़ी ट्रक से करीब 400 लीटर डीजल चोरी का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस गश्त की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ति इरशाद अहमद ने बताया कि 19 अप्रैल की रात ट्रक घर के सामने खड़ी थी, जिसमें हजारों रुपये का डीजल भरा था। आरोप है कि तड़के करीब 3:34 बजे कुछ लोग वाहन लेकर पहुंचे और टंकी से डीजल निकालकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें आरोपी आराम से वारदात करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद 112 पर सूचना दी गई, लेकिन चोर आसानी से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डांस करती हुई लड़कियों को चुड़ैल बोला...बरेली का रीलबाज हसन अरेस्ट, क्या बोली मां?

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी ने एक युवक को जेल पहुंचा दिया। यहां कंजादासपुर इलाके के रहने वाले हसन खान पर आरोप है कि उसने हिंदू महिलाओं के डांस वीडियो पर अभद्र टिप्पणी की थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हसन को गिरफ्तार कर लिया।

वायरल वीडियो में दिखता है कि बैंड-बाजे की धुन पर कुछ लड़कियां सड़क पर डांस कर रही हैं। हसन की कार इस वजह से ट्रैफिक जाम में फंसी दिखती है। इसी दौरान लड़कियों का वीडियो बनाते हुए हसन कहता है कि देखों कैसे चुड़ैलें डांस कर रही हैं। हसन पेशे से ड्राइवर है, लेकिन

सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौकीन है।

हसन पहले वह एक यूट्यूब चैनल से भी जुड़ा रहा, जहां उसकी कुछ पुलिसकर्मियों से पहचान हो गई थी। इसी दौरान उसने पुलिस की जैकेट हासिल कर ली और कई बार उसे पहनकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। हसन की मां का कहना है कि वह यह सब सिर्फ दिखावे और शौक के लिए करता था, लेकिन उसकी यही आदत अब उसके लिए मुसीबत बन गई। यह कोई अपराधी नहीं है।

मेरे बेटे से गलती हुई, उसे माफ कर दीजिए- मां की गुहार

हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब जेल भेज दिया। हसन की मां सहाना का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बेटे के लिए हाथ जोड़कर माफी की अपील की। मां सहाना का कहना है कि उनका बेटा कोई अपराधी नहीं है, बल्कि एक आम लड़का है जो बहकावे में आकर गलती कर बैठा। उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरा बेटा अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी भूल हो गई है। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा देना ठीक नहीं है। सहाना का कहना है कि हसन को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। हसन के पिता गुलफाम मजदूरी करते हैं और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। मां का कहना है कि बेटे के जेल जाने से घर की हालत और खराब हो गई है।

भाई ने भी मानी गलती

हसन के छोटे भाई फैजान ने भी माना कि उसके भाई से गलती हुई है। उसने कहा, जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब वह अपनी गलती मान चुका है। हम चाहते हैं कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वह सुधर सके। फैजान ने बताया कि हसन घर का बड़ा बेटा है और उसकी कमाई से परिवार को सहारा मिलता था। परिवार अब प्रशासन और लोगों से यही उम्मीद कर रहा है कि हसन को सुधार का एक मौका दिया जाए।

बदल जाएगी लोनी की सूरत... 30 मीटर तक चौड़ी होंगी सड़के, नहीं लगेगा जाम

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के हालात बदले वाले हैं। लंबे समय से अव्यवस्थित शहरी विस्तार, अवैध कॉलोनियों और भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे इस इलाके की सूरत बदलने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक नई योजना तैयार की है। इलाके को सुनियोजित करने के लिए जीडीए ने मिनी पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत पूरे इलाके को नया रूप दिया जाएगा और व्यवस्थित किया जाएगा।

लोनी में अनियोजित बसावट और जर्जर सड़कों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि विकास योजनाएं भी जाम और अव्यवस्था में फंसकर रह जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने महायोजना-2031 के तहत सड़क कनेक्टिविटी को आधार

बनाकर एक नया ढांचा तैयार किया है। इस योजना में टीला मोड़ से पाइपलाइन रोड और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले नए मार्ग विकसित किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि अंदरूनी इलाकों तक पहुंच भी आसान होगी।

तीन चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक मजबूत सड़क नेटवर्क बनाने की योजना है। जीडीए के मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क की चौड़ाई 30 मीटर तय की गई है, लेकिन शुरुआत 15 मीटर चौड़ी सड़क से की होगी ताकि काम जल्दी शुरू हो सके और लोगों को तत्काल राहत मिल सके। प्रोजेक्ट के पहले फेज में टीला मोड़ से भारत सिटी के आगे तक 1400 मीटर लंबी सड़क, दूसरे फेज में पाइपलाइन रोड से 1270 मीटर लंबी सड़क जोड़ी जाएगी और तीसरे फेज में 550 मीटर लंबी कनेक्टिविटी सड़क बनाई जाएगी।

अवैध कॉलोनियों पर लगेगी रोक

इस योजना का एक अहम पहलू यह भी है कि सड़क बनने के बाद अवैध कॉलोनियों के अनियंत्रित फैलाव पर लगाम लगाई जा सकेगी। अभी तक कनेक्टिविटी की कमी और स्पष्ट प्लानिंग के अभाव में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब सड़क किनारे वैध नक्शा पास कराने की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे लोगों को भी नियमों के तहत निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अधिग्रहण की जाएगी जमीन

परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी सहमति से किया जाएगा और इसके बदले भूमि स्वामियों को एफएआर जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं। अलग-अलग चरणों के लिए करोड़ों रुपये का बजट भी तय किया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ सड़क बनाना नहीं, बल्कि पूरे लोनी क्षेत्र को एक व्यवस्थित शहरी ढांचे में ढालना है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो आने वाले समय में इसी मॉडल को अन्य अव्यवस्थित इलाकों में भी लागू किया जा सकता है।

किन गांवों को अधिग्रहण में किया जाएगा शामिल?

प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में टीला शहबाजपुर, निस्तौली, नारायण नगर, अफजलपुर, शरीफाबाद और असालतपुर सहित कई गांवों को शामिल किया जा सकता है। पहले फेज में करीब 0.6488 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिस पर करीब 16.95 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है। वहीं दूसरे फेज में करीब 11.75 करोड़ रुपये और तीसरे चरण में करीब 19.08 करोड़ रुपये का बजट अनुमानित किया गया है।

अजय यादव ने जनपद का मान महाराष्ट्र में बढ़ाया: सपा

जौनपुर। विधानसभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम रमदेईया निवासी अजय यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबु आसिम आजमी द्वारा समाजवादी महाराष्ट्र प्रदेश का पुनः उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आज प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर प्रथम जनपद आगमन पर नगर के मंगलम लॉन मियांपुर में भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अजय यादव का जनपद की तरफ से जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य, पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव महासचिव आरिफ हबीब ने बुके देकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया।तत्पश्चात उपस्थित सपाजनों ने क्रमवार माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि स्वागत सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नवमनोनित प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि आज आप द्वारा स्वागत सम्मान किया।

अधिवक्ताओं ने डीएम से तहसीलदार की शिकायत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को मछलीशहर तहसील के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र से तहसीलदार रवि रंजन कश्यप और नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत की है। अधिवक्ताओं ने दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार रवि रंजन कश्यप और नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। उनके अनुसार, बिना धन उगाही के किसी भी पत्रावली पर निर्णय नहीं लिया जाता और मोल-भाव किया जाता है। कई पत्रावलियां छह से आठ महीने तक आदेश के लिए लंबित रखी जाती हैं।शिकायत में यह भी कहा गया है कि ये अधिकारी न तो जनता दर्शन में बैठते हैं और न ही किसी प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हैं। छात्र-छात्राओं के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों पर भी आख्या नहीं मांगी जा रही है, जिससे कई छात्रों की प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है और वे परेशान हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि हर न्यायालय में निजी मुंशी काम कर रहे हैं, जबकि शासन का सख्त आदेश है कि निजी कर्मचारियों को न्यायालयों से हटाया जाए। इसके अतिरिक्त, बिना किसी पूर्व सूचना के अधिवक्ताओं की मेज-कुर्सियां फेंककर तोड़ दी गईं और पंखे भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए।तहसीलदार पर न्यायालय के पश्चिम में स्थित सार्वजनिक शौचालय को भी ताला लगवाकर बंद करवाने का आरोप है, जबकि यह जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति का हवाला देते हुए कहा कि इन अधिकारियों के कारण शासन-प्रशासन की छवि खराब हो रही है।

क्या खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए नुकसानदायक है

अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है। बल्कि सही तरीके से पानी पीना भी जरूरी है। ऐसे में अक्सर ये सवाल रहता है कि पानी खड़े होकर पीना चाहिए या नहीं। कई लोगों को मानना है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द या कमजोरी की समस्या हो सकती है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ मिथक है। जब हम इस विषय को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। आज के समय में जहां हर आदत को हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है, वहीं पानी पीने का तरीका भी चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोग मानते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से शरीर पर दबाव पड़ता है और जोड़ों पर असर होता है, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक मिथक बताते हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि क्या खड़े होकर पानी पीना क्या सच में घुटनों के लिए नुकसानदायक है या यह सिर्फ एक पारंपरिक मान्यता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। यहां हम एक्सपर्ट और रिसर्च के आधार जानेंगे कि इसकी क्या सच्चाई है।

क्या खड़े होकर पानी पीना घुटनों पर असर डालता है?

पबमेड की रिसर्च के मुताबिक, खड़े होकर पानी पीने का असर शरीर पर हो सकता है लेकिन घुटनों पर नहीं। इस रिसर्च में पानी पीने के बाद ब्लड प्रेशर और स्टेंडिंग रिस्पॉन्स को देखा गया। खड़े होकर पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन पर पर असर पड़ता है। लेकिन घुटनों या joints पर कोई नुकसान नहीं सामने आया है।

क्या कहती है स्टडी?

स्टडी बताती है कि पानी पानी शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन कैसे पिया जा रहा है इसका कोई खास प्रभाव नहीं बताया गया है। हालांकि, पीएसी की रिपोर्ट बताती है कि कुछ लोगों को खड़े होकर पानी पीने दिया गया तो उनके शरीर में फ्ल्यूड मेजरमेंट में थोड़े बदवाव आए। लेकिन पैर या ज्वाइंट में कोई नुकसान नहीं पाया गया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो रिसर्च बताती है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द या arthritis का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में पानी जमा हो जाता है।

एक्सपर्ट की राय भी जानें

दिल्ली के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट डॉ। सक्षम मित्तल बताते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं, यह बात सच नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मिथक है। पानी पीने का तरीका घुटनों पर सीधे असर नहीं डालता। शरीर की पाचन प्रक्रिया ऐसी होती है कि पानी किसी भी स्थिति में पेट तक सामान्य रूप से पहुंच जाता है। हालांकि, बैठकर और धीरे-धीरे पानी पीना एक अच्छी आदत मानी जाती है। इससे शरीर पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और पेट से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों से भी बचाव होता है। खड़े होकर जल्दी-जल्दी पानी पीने से कुछ लोगों को गैस या भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन इसका घुटनों से कोई लेना-देना नहीं है। घुटनों की समस्या आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस, बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन या कम एक्सरसाइज की वजह से होती है। इसलिए इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप खड़े होकर पानी पीते हैं या बैठकर। बस ध्यान रखें कि दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।

कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए जरूरी आउटफिट्स कौन से हैं?

कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए जींस–टीशर्ट, कुर्ती–लेगिंग्स, डेनिम जैकेट, फ्लोरल ड्रेस और पलाज़ो–टॉप जैसे आउटफिट्स जरूरी हैं, जो कम्फर्टेबल और स्टाइलिश दोनों होते हैं।

कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी पर्सनालिटी दिखाने का भी एक शानदार मौका होती है। ऐसे में सही आउटफिट का चुनाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपको स्टाइलिश लुक दे सकता है।

हर दिन कॉलेज के लिए क्या पहनें, यह सवाल लगभग हर लड़की के मन में आता है। कभी कुछ ज्यादा ओवरड्रेस्ड लगने का डर होता है, तो कभी बहुत सिंपल दिखने का। इसलिए जरूरी है कि आपकी अलमारी में कुछ ऐसे मस्ट-हैव आउटफिट्स हों, जो हर मौके पर काम आएं और आसानी से स्टाइल किए जा सकें।

आजकल फैशन सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करने का नाम नहीं है, बल्कि आराम और स्टाइल का सही संतुलन बनाना भी जरूरी है। खासकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए ऐसे कपड़े जरूरी हैं जो पूरे दिन आरामदायक होने के साथ-साथ ट्रेंडी भी लगें। यहां हम आपको बताएंगे 5 ऐसे आउटफिट्स, जो हर कॉलेज गर्ल के वॉर्डरोब में होने चाहिए, ताकि आप हर दिन स्टाइलिश और आत्मविश्वासी नजर आएं।

क्लासिक जींस और टी-शर्ट

जींस और टी-शर्ट का कॉम्बिनेशन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। यह सिंपल, आरामदायक और हर दिन के लिए परफेक्ट है। आप इसे स्नीकर्स और बैकपैक के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

कुर्ती और लेगिंग्स

अगर आप एथनिक टच चाहती हैं, तो कुर्ती और लेगिंग्स एक बेहतरीन विकल्प है। यह लुक एलिगेंट और कम्फर्टेबल दोनों होता है, खासकर गर्मियों में इस तरह के आउटफिट बेस्ट रहते हैं।

डेनिम जैकेट के साथ कैज़ुअल आउटफिट

डेनिम जैकेट आपके किसी भी सिंपल आउटफिट को स्टाइलिश बना सकती है। टी-शर्ट और जींस या ड्रेस के साथ इसे पहनकर आप कूल लुक पा सकती हैं।

फ्लोरल ड्रेस

फ्लोरल ड्रेस आपको फ्रेश और ट्रेंडी लुक देती है। यह कॉलेज के फंक्शन्स या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए परफेक्ट है।

पलाजो और टॉप

पलाज़ो और टॉप का कॉम्बिनेशन आजकल काफी ट्रेंड में है। यह स्टाइलिश होने के साथ-साथ बेहद आरामदायक भी होता है, जिससे आप पूरे दिन सहज महसूस करती हैं।

स्टाइल टिप्स

हमेशा कम्फर्ट को प्राथमिकता दें
एक्सेसरीज को ओवरडू न करें
अपने बॉडी टाइप के अनुसार कपड़े चुनें

क्या शाम होते ही ऊर्जा का स्तर हो जाता है कम? ये हो सकते हैं कारण

आपका दिन किस तरह से बीतता है, यह आपके ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करता है। अगर आप शाम होते ही सुस्त और थकान महसूस करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें शामिल हैं, जो आपके शरीर और मन को कमजोर कर रही हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो शाम होते ही आपके शरीर और मन को सुस्त कर सकती हैं।

दोपहर का खाना ठीक से न खाना

दोपहर का खाना न खाना या इसे छोड़ देना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। अगर आप दोपहर का खाना नहीं खाते हैं तो शाम को आपको अधिक भूख लगेगी और आप जो भी खाएंगे, उससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। वहीं दोपहर का खाना खाने से आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है और आप अधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए, दिनभर में एक बार जरूर भरपेट खाना खाएं।

अधिक चाय या कॉफी पीना

कई लोग दिनभर में कई बार चाय या कॉफी पीते हैं। ये पेय आपको थोड़े समय के लिए ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने से नींद में खलल पड़ सकता है और रात को नींद आने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त इनका अधिक सेवन शरीर के डिहाइड्रेट होने का कारण भी बन सकता है।

देर से सोने की आदत

देर से सोने की आदत भी आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप रोजाना देर से सोते हैं तो आपका शरीर ठीक से आराम नहीं कर पाता और अगले दिन आपको थकान महसूस होती है। इसलिए, कोशिश करें कि आप हर दिन एक ही समय पर सोएं और 7 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि आपका शरीर ठीक से आराम कर सके और आप अगले दिन तरोताजा महसूस करें।

अधिक चिंता करना

चिंता भी आपके ऊर्जा स्तर को कम करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप रोजाना किसी न किसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं तो इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और आप शाम होते ही सुस्त महसूस करने लग सकते हैं। इसलिए, चिंता को कम करने के लिए रोजाना कुछ मिनट ध्यान या योग करें और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों।

शारीरिक गतिविधियों की कमी

शारीरिक गतिविधियों की कमी भी आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप रोजाना थोड़ी बहुत व्यायाम नहीं करते हैं तो आपका शरीर सुस्त हो सकता है और आपको शाम होते ही थकान महसूस होने लग सकती है। इसलिए, रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें, जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना या तैराकी आदि। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे।

कामकाजी महिलाओं के लिए समय की बचत से जुड़े ये 5 टिप्स हो सकते हैं लाभदायक

आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, फिर चाहे वह ऑफिस हो या घर हो। कामकाजी महिलाओं के लिए समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। सही समय प्रबंधन से महिलाएं अपने कामों को आसानी से पूरा कर सकती हैं और तनावमुक्त रह सकती हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार सुझाव जानेंगे, जो कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।

प्राथमिकता तय करें

सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन-से काम सबसे ज्यादा अहम हैं और उन्हें पहले करना चाहिए। इसके लिए आप एक सूची बना सकती हैं, जिसमें सबसे जरूरी काम ऊपर हों और कम जरूरी नीचे। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कौन-से काम बाद में किए जा सकते हैं। इससे आपका समय सही तरीके से बंटेगा और आप तनावमुक्त रहेंगी।

अलार्म का उपयोग करें

अपने मोबाइल या घड़ी पर अलार्म सेट करें ताकि आप समय पर हर काम कर सकें। इससे आप किसी भी काम में देरी नहीं होंगी और सब कुछ समय पर पूरा होगा। अलार्म का उपयोग करने से आप अपने दिनचर्या को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगी और किसी भी काम को भूलने से बच सकेंगी। यह आदत आपके समय प्रबंधन को सुधारने में बहुत मददगार साबित हो सकती है।

छोटे-छोटे ब्रेक लें

काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ताकि आप थकान महसूस न करें। 50 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान थोड़ी टहलें या कुछ हल्का खाएं, जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप फिर से ताजगी से काम कर सकेंगी। ब्रेक लेने से आपका ध्यान भी बेहतर रहेगा और आप ज्यादा उत्पादक बन सकेंगी। यह आदत आपको थकान से बचाएगी और आपके काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी।

एक समय में एक काम करें

एक साथ कई काम करने से अक्सर कोई एक काम ठीक से नहीं होता। इसलिए जितना संभव हो उतना एक समय में एक ही काम करें। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आपका काम जल्दी पूरा होगा। एक समय में एक काम करने पर आप हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगी और आपका समय भी बच सकेगा। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप कम तनाव में अधिक काम कर सकेंगी।

योजना बनाकर चलें

रोजाना सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लें कि आपको कौन-कौन से काम करने हैं और किस क्रम में करने हैं। इससे आपका दिन व्यवस्थित रहेगा और आपको किसी भी काम में परेशानी नहीं होगी। इन सरल लेकिन असरदार सुझावों को अपनाकर आप अपने समय प्रबंधन को बेहतर बना सकती हैं और अपने जीवन को संतुलित रख सकती हैं।

स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल नहीं होगा आधार एप, भारी विरोध के बाद सरकार ने लिया यू-टर्न

स्मार्टफोन यूजर्स और मोबाइल कंपनियों के लिए एक अहम खबर है। भारत सरकार ने स्मार्टफोन्स में आधार ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने के अपने प्रस्ताव को अब आधिकारिक तौर पर वापस लेने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब एप्पल, सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन कंपनियों को भारत में बिकने वाले अपने मोबाइल फोन्स में पहले से आधार ऐप डालकर देने की कोई जरूरत नहीं होगी। दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों के भारी विरोध के बाद एक सरकारी संस्था ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार अब इस प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं करेगी।

ढ्ढञ्ज मंत्रालय ने खारिज किया यूआईडीएआई का प्रस्ताव

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आधार का संचालन करने वाली सरकारी संस्था यूआईडीएआई (ढ्ढष्ठ्रढ्ढ) ने इसी साल जनवरी में आईटी मंत्रालय से संपर्क साधा था। यूआईडीएआई ने मंत्रालय से एप्पल, गूगल और अन्य प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ बातचीत कर आधार ऐप को फोन में प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने की मांग की थी। हालांकि, अब यूआईडीएआई ने अपने एक बयान में स्पष्ट कर दिया है कि आईटी मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की गहन समीक्षा की है और वह स्मार्टफोन पर इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि देश के करीब 1.34 अरब लोगों के पास 12 अंकों का यह यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जिसका इस्तेमाल बैंकिंग से लेकर एयरपोर्ट पर फास्ट एंट्री तक में किया जाता है।

दो साल में छठी बार सरकार का प्रयास हुआ फेल

यह कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार ने मोबाइल फोन में किसी सरकारी ऐप को अनिवार्य करने की कोशिश की हो। जानकारी के अनुसार, पिछले दो सालों में यह छठा मौका था जब सरकार की ओर से फोन पर किसी सरकारी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की मांग उठाई गई थी। हालांकि, मोबाइल कंपनियों ने एकजुट होकर सरकार के इन सभी छह प्रयासों का कड़ा विरोध किया है। ढ्ढष्ठ्रढ्ढ का कहना है कि आईटी मंत्रालय ने इस आधार प्री-इंस्टॉलेशन प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द करने का अंतिम फैसला लेने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तार से परामर्श किया था।

कंपनियों ने दिया सुरक्षा और बढ़ती लागत का हवाला

आधार प्रीलोड का यह प्रस्ताव मिलते ही स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनियों में खलबली मच गई थी। कंपनियों ने सरकार के सामने डिवाइस की सुरक्षा और सॉफ्टवेयर की कम्पैटिबिलिटी को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर कीं। इसके अलावा, मोबाइल निर्माताओं का सबसे बड़ा तर्क उत्पादन लागत (प्रोडक्शन कॉस्ट) बढ़ने को लेकर था। कंपनियों का कहना था कि इस नियम के लागू होने से उन्हें भारतीय बाजार और निर्यात किए जाने वाले बाजारों के लिए अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइनें लगानी पड़ेंगी, जिससे उनका खर्च काफी बढ़ जाएगा। विशेष रूप से एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने इस प्रस्ताव को लेकर डिवाइस की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े कई अहम सवाल उठाए थे, जिसके बाद आखिरकार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।

बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका, बिना किसी गारंटी के सरकार दे रही 20 लाख तक का मुद्रा लोन

अगर आप अपना खुद का छोटा कारोबार शुरू करने या पुराने बिजनेस को रफ्तार देने का सपना देख रहे हैं, तो केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार करने वालों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इस शानदार योजना का मुख्य उद्देश्य देश में उद्यमिता को बढ़ावा देना और पूंजी की कमी से जूझ रहे लोगों को आसान शर्तों पर फाइनेंस उपलब्ध कराना है।

क्या है मुद्रा लोन योजना और कैसे मिलता है लाभ?

मुद्रा लोन योजना मुख्य रूप से गैर-कॉर्पोरेट और छोटे व्यवसायों की आर्थिक मदद के लिए तैयार की गई है। इसके तहत देश के विभिन्न बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थान और एनबीएफसी आसानी से कर्ज मुहैया कराते हैं। इस योजना को शिशु, किशोर और तरुण नाम की तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। समय के साथ कारोबारियों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके और वे अपने व्यवसाय को नया मुकाम दे सकें।

बिना कुछ गिरवी रखे मिलता है कर्ज, बस चाहिए ये पांच कागजात

इस सरकारी योजना की सबसे बड़ी और अहम खासियत यह है कि इसमें आवेदक को बैंक के पास कोई संपत्ति गिरवी (कोलैटरल) रखने या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार खुद क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देती है, जिसके चलते बैंक आसानी से लोन पास कर देते हैं। इस लोन के लिए आवेदन करते समय कुछ बुनियादी दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनमें आपकी पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी), पते का पुख्ता प्रमाण (बिजली बिल या राशन कार्ड), आपके बिजनेस का पूरा प्लान, पिछले 6 से 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। हालांकि, बैंक लोन मंजूर करने से पहले आवेदक का प्रोफाइल और उसकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री (सिबिल स्कोर) जरूर परखते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करें आवेदन

छोटे दुकानदार, कारीगर, महिला उद्यमी और स्टार्टअप चलाने वाले लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस लोन पर ब्याज दरें विभिन्न बैंकों के नियमों के अनुसार तय होती हैं, जो आमतौर पर 8त्न से 12त्न के बीच रहती हैं। इसके भुगतान के लिए 3 से 5 साल तक का पर्याप्त समय दिया जाता है, जिससे हर महीने ईएमआई का बोझ कारोबार पर भारी नहीं पड़ता। लोन लेने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। आवेदक अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर या घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में कई बैंक तो बहुत ही कम समय में लोन अप्रूव कर रहे हैं, जिससे लोगों के समय की भारी बचत हो रही है। यह योजना न केवल स्वरोजगार को पंख दे रही है, बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है।

भारत में मजबूरी तो अमेरिका में मजे की नौकरी है डिलीवरी का काम, हर महीने आसानी से हो रही 6 लाख रुपए की कमाई

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में डिलीवरी ब्वॉय के काम को अक्सर एक बेहतर करियर विकल्प के तौर पर नहीं देखा जाता है और इसमें कड़ी मेहनत के बाद भी औसतन 25-30 हजार रुपये महीने की ही कमाई हो पाती है। लेकिन, अमेरिका जैसे विकसित देश में यह काम मजबूरी नहीं बल्कि एक मजे की नौकरी माना जाता है। वहां यह काम इतना सुविधाजनक और फायदेमंद है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसे शौक से कर रही हैं। अमेरिका में डिलीवरी का काम एक बेहतरीन पार्ट टाइम जॉब के रूप में उभरा है, जहां लोग दिन के कुछ ही घंटे काम करके लाखों रुपये की शानदार कमाई कर रहे हैं।

हर महीने 5 से 6 लाख रुपये की होती है शानदार आमदनी

अगर यह कहा जाए कि अमेरिका में डिलीवरी का काम करके कोई महीने में 5 से 6 लाख रुपये आसानी से कमा सकता है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह काफी हैरानी भरा लगता है। वहां लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोग इसे फुल-टाइम यानी करीब 8 घंटे करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग केवल 4 घंटे देकर ही अपनी जरूरत भर के पैसे जुटा लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वहां एक डिलीवरी पर्सन औसतन 20 से 25 डॉलर प्रति घंटा कमा लेता है। 4 घंटे के काम में ही लोग करीब 9000 रुपये (100 डॉलर) तक कमा लेते हैं। वहीं, फुल टाइम काम करने वाले रोजाना 200-220 डॉलर यानी करीब 20 हजार रुपये आसानी से बना लेते हैं, जिससे उनकी मासिक आय 5 से 6 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

स्मार्ट तरीके से काम कर बढ़ाते हैं अपना मुनाफा

अमेरिका में डिलीवरी करने वाले लोग अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मल्टी-ऐप तकनीक का बड़ा ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे एक ही समय में 'उबर ईट्स' और 'डोरडैश' जैसे कई ऐप चालू रखते हैं और उसी ऑर्डर को स्वीकार करते हैं जिसमें कम दूरी तय करनी हो और पैसे ज्यादा मिल रहे हों। इससे उनके खाली बैठने का समय कम हो जाता है। इसके अलावा, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे महंगे और व्यस्त शहरों में प्राइम लोकेशन और पीक आवर्स के दौरान ऑर्डर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। लंच, डिनर (रश आवर्स) या वीकेंड के समय काम करने से उन्हें कंपनियों की तरफ से 'सर्ज प्राइजिंग' और अच्छा बोनस मिलता है, जिससे उनकी कमाई में भारी उछाल आ जाता है।

टिप कल्चर भी है बंपर कमाई का बड़ा जरिया

अमेरिका में लोगों के बीच सर्विस के बदले टिप देने का एक मजबूत कल्चर है, जो इन डिलीवरी ड्राइवर्स की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा साबित होता है। कई बार तो इन लोगों को डिलीवरी फीस से कहीं ज्यादा पैसे सिर्फ टिप के जरिए ही मिल जाते हैं। छोटे शहरों में जहां 10 से 15 डॉलर तक की टिप मिलना एक आम बात है, वहीं बड़े और महंगे शहरों में ग्राहकों की तरफ से 30 डॉलर तक की टिप भी आसानी से दे दी जाती है। अच्छे इलाके, पीक आवर्स, बोनस और भारी-भरकम टिप को मिला दिया जाए तो यहां डिलीवरी ड्राइवर्स 30 डॉलर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं।

भीषण गर्मी ने तोड़ा कृषि चक्र, 100 करोड़ लोगों पर संकट, संयुक्त राष्ट्र ने चेताया

रोम, एजेंसी। भीषण गर्मी वैश्विक कृषि प्रणालियों को तबाही की कगार पर धकेल रही हैं। इससे वैश्विक खाद्य तंत्र बिगड़ने लगा है। इसके चलते दुनियाभर में 100 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका और उनके स्वास्थ्य पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, बल्कि खेती, मछली पालन और वानिकी के लिए एक अस्तित्वगत खतरा बन गई है। एफएओ के जलवायु परिवर्तन कार्यालय के प्रमुख कावेह जाहेदी ने कहा, भीषण गर्मी यह तय कर रही है कि किसान और मछुआरे क्या उगा सकते हैं और कब काम कर सकते हैं। एजेंसी

गर्मी का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दुनिया के 91 फीसदी महासागरों ने कम से कम एक समुद्री लू का सामना किया। इससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, जिससे मछलियों का अस्तित्व खतरे में है और समुद्री खाद्य प्रणालियां चरमरा रही हैं।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता

कृषि से संबंधित रिपोर्ट में बताया गया कि किसानों को मौसम का सटीक डेटा समय पर मिलना चाहिए ताकि वे बुवाई और कटाई के समय में बदलाव कर सकें। अगर तापमान 1.5 डिग्री के बजाय 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, तो भीषण गर्मी की तीव्रता और आवृत्ति चार गुना तक बढ़ सकती है।

चार प्रमुख फसलों पर पड़ता है असर

वैश्विक औसत तापमान में प्रत्येक एक डिग्री की वृद्धि से चार प्रमुख फसलों मक्का, चावल, सोयाबीन और गेहूं की पैदावार में लगभग 6% की कमी आती है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 अब तक के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक रहा है। जब तापमान 30 डिग्री की सीमा को पार कर जाता है, तो प्रमुख फसलों की पैदावार में तेजी से गिरावट आने लगती है।

'लश्कर-जैश पर नकेल कसे पाकिस्तान'

पहलगाम हमले की बरसी पर अमेरिकी सांसदों ने एकसुर में उठाई मांग

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने आतंकवाद की मानवीय कीमत विषय पर एक प्रदर्शनी लगाई थी। इस दौरान शर्मन ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को याद किया। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे।

शर्मन ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ था, जिसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। खबरों के मुताबिक, इन समूहों को पाकिस्तान में पनाह मिलती है। डेमोक्रेट नेता शर्मन ने मांग की कि पाकिस्तानी सरकार को इन आतंकी गुटों पर नकेल कसने की मांग की। यह प्रदर्शनी ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान खुद को शांतिदूत के रूप में पेश कर रहा है और अमेरिका-ईरान युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है।

डिजिटल प्रदर्शनी में क्या?

इस डिजिटल प्रदर्शनी में 1993 के मुंबई बम धमाकों, 2008 के मुंबई हमलों और पहलगाम हमले की तस्वीरें दिखाई गईं। इसमें उन आतंकी संगठनों और लोगों की पहचान भी उजागर की गई जो पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि आतंकवाद मानवता को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को दोहराया जिसमें भारत आतंकवाद को हराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रदर्शनी में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के कई बड़े सांसद शामिल हुए। इस दौरान सांसद लिसा मैक्लेन ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना और मिलकर काम करना ही सही रास्ता है। वहीं, सांसद रो खन्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने 1990 के दशक में ही इस खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन तब कम ही लोगों ने इसे गंभीरता से लिया था।

ऑपरेशन सिंदूर का भी हुआ जिक्र

इस दौरान 7 मई 2025 को भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में लश्कर और जैश के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच करीब 88 घंटे तक सैन्य संघर्ष चला था, जो 10 मई की शाम को थमा। सांसद रिचर्ड मैककॉर्मिक ने आतंकवाद को एक अनोखी बुराई बताया जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा से हमारी विविधता को खत्म करना चाहते हैं, वे ही असली दुश्मन हैं।

ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने अचानक छोड़ा पद, हंग काओ बने कार्यवाहक सचिव

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पेंटागन ने बुधवार को अचानक घोषणा की कि नौसेना सचिव जॉन फेलन अपना पद छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी सैन्य सेवा के प्रमुख का यह पहला इस्तीफा है। हालांकि, रक्षा विभाग में पिछले कुछ समय से कई बड़े अधिकारियों को हटाया जा रहा है।

फेलन के अचानक हटने का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है और दुनिया भर में तेहरान से जुड़े जहाजों को निशाना बना रही है। अब ट्रंप के करीबी और अंडरसेक्रेटरी हंग काओ नौसेना के कार्यवाहक सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। काओ नौसेना में 25 साल तक रहे हैं और उनके पास युद्ध का अनुभव भी हैं।

फेलन का पद से हटना पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल की एक लंबी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया था। हेगसेथ ने पिछले साल पद संभालने के बाद से कई जनरलों और एडमिरलों को हटाया है। इनमें एडमिरल लीसा फ्रेंचेती और जनरल जिम स्लाइफ भी शामिल हैं। ट्रंप ने जनरल चार्ल्स सीक्यू ब्राउन जूनियर को भी उनके पद से हटा दिया है।

फेलन का इस्तीफा बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने मंगलवार को ही वाशिंगटन में नौसेना के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने पत्रकारों से अपने एजेंडे पर बात की थी। उन्होंने सांसदों के साथ बजट और नए जहाज बनाने की कोशिशों पर भी चर्चा की थी। हालांकि, पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि फेलन तुरंत अपना पद छोड़ रहे हैं।

बता दें कि फेलन ने पहले कभी सेना में काम नहीं किया था। उन्हें नौसेना में बड़े बदलाव करने के लिए लाया गया था। वे एक निजी निवेश कंपनी के संस्थापक भी रहे हैं। फेलन ऐसे समय में जा रहे हैं जब नौसेना बहुत व्यस्त है। उसके तीन विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में तैनात हैं। साथ ही नौसेना कैरिबियन में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है। जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने में भी नौसेना की अहम भूमिका थी। नए कार्यवाहक सचिव हंग काओ वियतनाम से आए शरणार्थी हैं। 1970 के दशक में जब वे बच्चे थे, तब अपने परिवार के साथ वियतनाम से भागकर अमेरिका आ गए थे। उन्होंने वर्जीनिया से सीनेट का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। काओ सेना में विविधता (डीईआई) कार्यक्रमों और कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के कड़े विरोधी रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर भी सवाल उठाए थे। काओ ने नौसेना अकादमी से पढ़ाई की है और इराक, अफगानिस्तान और सोमालिया में अपनी सेवाएं दी हैं।

फारस की खाड़ी–होर्मुज में तेल रिसाव का खतरा ; उपग्रह तस्वीरों में लावान द्वीप से कुवैत तट तक असर दिखा

दुबई, एजेंसी। अमेरिका और ईरान से जुड़े सैन्य हमलों के बाद फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में कई बड़े तेल रिसाव अंतरिक्ष से दिखाई दिए हैं। उपग्रह तस्वीरों में ईरान के केश्म द्वीप, लावान द्वीप और कुवैत तट के पास समुद्र में फैला तेल साफ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता, तटीय आबादी और पेयजल आपूर्ति के लिए बड़े पर्यावरणीय संकट में बदल सकता है।

सीएनएन के अनुसार उपग्रह चित्रों ने न केवल तेल सुविधाओं और जहाजों पर हमलों से हुई क्षति को उजागर किया है बल्कि फारस की खाड़ी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर मंडरा रहे खतरे को भी सामने रखा है। इस क्षेत्र में फैला तेल तटीय समुदायों की आजीविका, मछली पालन, समुद्री जीवों और समुद्री जल को मीठा बनाने वाले संयंत्रों तक को प्रभावित कर सकता है। एक सैटेलाइट तस्वीर में ईरान के केश्म द्वीप के पास होर्मुज जलडमरूमध्य में पांच मील से अधिक क्षेत्र में फैला तेल देखा गया।

संरक्षित शिदवर द्वीप की जैव विविधता पर खतरा

शिदवर द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित एक कोरल द्वीप है। यह कछुओं, समुद्री पक्षियों और अन्य वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल रिसाव ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने पर समुद्री जीवों के प्रजनन, भोजन श्रृंखला और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक असर डाल सकता है। छह अप्रैल को कुछ उपग्रह तस्वीरों में कुवैत के तट के पास भी तेल फैला दिखाई दिया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा था कि उसने उसी दिन खाड़ी देशों की ईंधन और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं को निशाना बनाया।

जीव-जंतुओं समेत लाखों लोगों पर खतरा

डच शांति संगठन पैक्स के परियोजना प्रमुख विम ज्वाइनेनबर्ग ने चेतावनी दी कि इन तेल रिसावों का असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है, खासकर ईरान के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर। मछलियों के प्रदूषित होने से मछुआरों की आय और खाद्य सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं। यह तेल समुद्री कछुओं, डॉल्फिन और व्हेल जैसे जीवों के लिए भी गंभीर खतरा है। ये जीव या तो तेल निगल सकते हैं या उसमें फंस सकते हैं। इसके अलावा समुद्री जल को साफ कर पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स भी प्रभावित हो सकते हैं।

क्या है भू-अर्जन संशोधन, जिससे किसानों को होने वाला है बंपर फायदा

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ। मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बना रही है। मंत्रि-परिषद की बैठक में कृषि भूमि के अर्जन पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे जहां किसानों को नई जमीन खरीदने में आसानी होगी, वहीं भू-अर्जन कार्यों के निराकरण को गति मिलेगी। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को इसका लाभ होगा। यह किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री डॉ। यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया है। इससे किसानों को बाजार मूल्य का अधिकतम 4 गुना मुआवजा मिल सकेगा।

तेज होगा परियोजनाओं का क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री डॉ। यादव ने कहा कि इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिल सकेगी। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

मेट्रोपोलिटन सिटी की जरूरतें होंगी पूरी

मुख्यमंत्री डॉ। यादव ने कहा कि हम मध्यप्रदेश में मेट्रोपोलिटन सिटी की ओर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में भू-अर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। गत तीन वर्ष में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजना के माध्यम से 16 हजार करोड़ मुआवजा वितरित किया गया है। सालाना आधार पर यदि देखें तो जो मुआवजा करीब 5000 करोड़ रूपए था, अब वो 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अब हर साल करीब 20 हजार करोड़ रूपए मुआवजा किसानों को मिलेगा।

मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन

मुख्यमंत्री डॉ। यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष-2026 में किसानों के हित में निरंतर कार्य होगा। वैश्विक परिदृश्य में गेहूं का निर्यात न के बराबर है। इन परिस्थितियों में भी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पहले छोटे और मझौले किसान और फिर बड़े किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। पिछले साल का गेहूं भी वेयरहाउस में स्टॉक है। इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है। अन्नदाताओं के हित में राज्य सरकार गेहूं खरीदी का कार्य पूर्ण करेगी। भारत सरकार से 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी के अनुमान के अनुसार आवश्यक अनुरोध किया गया है।

लाड़ली बहनों की राशि में वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ। यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई है, किसानों और नारी सशक्तिकरण के लिए अपने सभी वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है। योजनाओं को बंद किए जाने संबंधी दुष्प्रचार गलत सिद्ध हुआ है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 21 हजार करोड़ रूपए का बजट पेश किया है। नीति आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार के वित्तीय प्रबंधन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।

महंगी किताबें खरीदने का दबाव, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के अलग-अलग हिस्सों से अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई। शिकायत में ये कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल उनपर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की तरफ से लगाए गए आरोप के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस मामले में प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह कार्यवाही नमो फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर की गई है।

आयोग ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के अनुपालन में जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने SCERT की तरफ से प्रकाशित पुस्तकों की संख्या तथा निजी एवं सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात संबंधी आंकड़े भी मांगे हैं।

आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि जब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को SCERT/NCERT की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो निजी स्कूलों में शुल्क के आधार पर इसी व्यवस्था को लागू करने में क्या बाधा है। आयोग के अनुसार, स्कूलों के प्राइवेटऔर सरकारी प्रबंधन के आधार पर पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम में अंतर करना अकादमिक भेदभाव की श्रेणी में आता है।

इसके साथ ही, शिक्षा मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कक्षा 8 तक परीक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, नामित अकादमिक प्राधिकरण से भिन्न क्यों है। आयोग के मुताबिक, स्कूलों के प्राइवेट और सरकारी प्रबंधन के आधार पर पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम में अंतर करना अकादमिक भेदभाव की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही, शिक्षा मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कक्षा 8 तक परीक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, नामित अकादमिक प्राधिकरण से अलग क्यों है।

अब आयुष्मान खुराना बनेंगे राजश्री के नए प्रेम, शरवरी संग ये प्रेम मोल लिया में करेंगे रोमांस, तय हुई रिलीज डेट

राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने अपनी नए प्रोजेक्ट का एलान किया है। 2022 में फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद सूरज बड़जात्या एक बार फिर एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म लेकर दर्शकों के बीच लौट आए हैं। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म के टाइटल के साथ, रिलीज डेट और लीड स्टार के नाम से भी पर्दा हटाया है।

राजश्री का चहेता किरदार प्रेम 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। राजश्री प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उनके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है।

राजश्री ने अपने नोट में लिखा है, हमारे पास एक अनाउंसमेंट है। इस नवंबर, राजश्री प्रोडक्शंस लिमिटेड, महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से, बड़े पर्दे पर एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहा है। सूरज आर। बड़जात्या की निर्देशित इस फिल्म का टाइटल है - ये प्रेम मोल लिया। इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं। यह हिमेश रेशमिया का एक म्यूजिकल है। थिएटर में 27 नवंबर 2026 को। तारीख याद रखें।

12 साल बाद सूरज बड़जात्या और हिमेश रेशमिया भी एक बार फिर साथ आ रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म प्रेम रतन धन पायो थी। अब जब हिमेश रेशमिया ये प्रेम मोल लिया के लिए म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, तो एक चार्ट-टॉपिंग गाने की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। बता दें, सूरज बड़जात्या की फिल्मों में संगीत एक बेहद अहम हिस्सा होता है।

आयुष्मान खुराना पहली बार प्रेम का किरदार निभाते दिखेंगे। आयुष्मान ने प्रेम की सादगी और मासूम शरारतों को, जो प्रेम की पहचान हैं, बहुत खूबसूरती से निभाते हुए दिखेंगे। उनके साथ जोड़ी में शरवरी हैं। यह उनकी पहली ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन होगा। वह अपनी परफॉर्मेंस में राजश्री हीरोइनों की खूबसूरती, हिम्मत और दम दिखाती नजर आएंगी। आयुष्मान खुराना और शरवरी की केमिस्ट्री और स्क्रीन प्रेजेंस देखने लायक होगा।

राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स की यह फिल्म दिवाली के बाद बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए उतरेगी। सूरज बड़जात्या की निर्देशित यह प्रेम मोल लिया 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दर्शकों का स्वागत करेगी।

मुनमुन दत्ता ने बताया समर मॉर्निंग रूटीन का राज, पेट की सेहत के लिए शेयर किए खास देसी ड्रिंक

गर्मियों का मौसम आते ही लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। खासतौर पर इस मौसम में पाचन संबंधी परेशानियां ज्यादा होती हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कई सेलेब्रिटीज भी अपने हेल्दी रूटीन को फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। इसी कड़ी में टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने अपने समर मॉर्निंग रूटीन की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की, जो अब खूब चर्चा में है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बना चुकीं मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वह सुबह की शुरुआत किस तरह से करती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी एक वीडियो और कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उनके हेल्दी नाश्ते की झलक देखने को मिल रही है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैंने सुबह के लिए एक ऐसी ड्रिंक तैयार की है, जो पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनमुन छाछ से कुछ बना रही हैं, जिसे वह पेट की सेहत के लिए बेहतरीन ड्रिंक बता रही हैं। इसे बनाते समय उन्होंने उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरा धनिया समेत कई चीजों को मिलाया।

इसके अलावा, मुनमुन ने एक तस्वीर के जरिए एक और खास ड्रिंक के बारे में जानकारी दी, जिसे रागी अंबली कहा जाता है। उन्होंने कैप्शन में बताया, यह देसी पेय पाचन को बेहतर बनाता है। साथ ही यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने का भी काम करता है। यह शरीर को हल्का महसूस कराता है।

मुनमुन दत्ता अपने फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यायाम और योग से जुड़े वीडियो और तस्वीरें साझा करती रहती हैं। उनका मानना है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के साथ-साथ सही खानपान भी उतना ही जरूरी है। फैंस भी उनके इस हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी पसंद करते हैं।

कांतारा अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत का मिस्ट्री वाला वैनिटी पोस्ट, अगला कदम क्या है, सब कंफ्यूज़!

अपने करियर के दमदार फेज़ के बाद, रुक्मिणी वसंत ने एक ऐसा क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है कि इंडस्ट्री में हलचल मच गई है-थोड़ा सा टीज़, लेकिन असली राज़ पूरी तरह सीक्रेट! हाल ही में एक्टर ने अपनी वैनिटी से एक शांत सा, बिहाइंड-द-सीन्स झलक शेयर की, जो साफ-साफ तो कुछ नहीं बताती, लेकिन सेट पर होने का हिंट ज़रूर देती है। फोटो खुद में सिंपल थी, लेकिन टाइमिंग ऐसी कि फैंस और इंडस्ट्री वाले दोनों ही डिटेक्टिव मोड में चले गए—आखिर ये किस प्रोजेक्ट की शूटिंग चल रही है? रुक्मिणी की ये उड़ान उनके हालिया परफॉर्मेंस की जबरदस्त तारीफ के बाद और तेज़ हो गई है, जिसे उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। स्क्रीन पर उनकी पकड़ ने उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे एक्साइटिंग टैलेंट्स में शामिल कर दिया है। उनके सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स, जिसमें वो यश के साथ नज़र आएंगी और डायरेक्शन है गीतू मोहनदास का। फिल्म में रुक्मिणी 'मेलिसा' का किरदार निभा रही हैं—एक ऐसा कैरेक्टर जो रहस्यमयी है, इमोशनल लेयर्स से भरा है और कहानी के डार्क, फेयरीटेल जैसे वर्ल्ड का अहम हिस्सा है। फिल्म 4 जून 2026 को रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा, वो जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआरनील में भी दिखाई देंगी, जो प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड एक एक्शन ड्रामा है। इस पीरियड फिल्म में उनका रोल फीमेल लीड के तौर पर कन्फर्म हो चुका है। कन्नड़ सिनेमा में भी रुक्मिणी ने केवीएन प्रोडक्शन्स के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म साइन की है, जिसे हेमंत एम. राव डायरेक्ट कर रहे हैं—ये उनकी तीसरी कोलैबोरेशन होगी 'सप्ता सागरदाचे एलो' के बाद। फिलहाल, रुक्मिणी ने अपने पत्ते छुपा कर रखे हैं—बस एक छोटी सी वैनिटी झलक से सबको सस्पेंस में डाल दिया हैज और अब सबकी नज़र बस इसी पर है—आगे क्या?

जूनियर एनटीआर फैंस के लिए डबल सेलिब्रेशन, एनटीआरनील की नई रिलीज डेट आउट

एनटीआरनील 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। मनोरंजन की दुनिया की दो बड़ी ताकतें मैन ऑफ द मासेज जूनियर एनटीआर और केजीएफ व सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील जब एक साथ आ रहे हैं, तो यह तय है कि दर्शकों को पर्दे पर एक अनोखा और भव्य सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा।

जब से एनटीआरनील का ऐलान हुआ है, यह सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी हुई है। भारतीय सिनेमा की दो सबसे बड़ी ताकतों, जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील का साथ आना ही इसे 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों की कतार में खड़ा कर देता है। बढ़ते उत्साह के बीच, मेकर्स ने एक बेहद रोमांचक पोस्टर जारी किया है और फिल्म की पहली झलक को लेकर बड़ी घोषणा की है, जो एनटीआर के जन्मदिन पर 20 मई को रिलीज होगी।

पोस्टर में एनटीआर का स्टाइल और पावरफुल अवतार फिल्म को लेकर बनी चर्चा को और भी बढ़ा रहा है। 20 मई को आने वाली पहली झलक के साथ फिल्म का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एनटीआर के जन्मदिन के मौके पर रिलीज होने वाली यह झलक उन लाखों फैंस के लिए एक खास तोहफा होगी जो उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इसके अलावा, इस फिल्म के लिए एनटीआर के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको हैरान कर दिया है। उनके इस नए लुक की तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी हैं और फैंस के बीच तहलका मचा रही हैं। उन्हें इस तरह के लुक में पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

एनटीआर नील को प्रशांत नील की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्म बताया जा रहा है, जो एक शानदार सिनेमाई अनुभव का वादा करती है। केजीएफ और सालार जैसी बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद, फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि प्रशांत नील अब क्या नया लेकर आएंगे। मैन ऑफ द मासेज जूनियर एनटीआर के साथ उनका यह तालमेल भारतीय सिनेमा के सबसे ताकतवर मेल में से एक माना जा रहा है।

फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त हलचल है और फैंस हर छोटे अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। दो इतने बड़े नामों के साथ आने से यह फिल्म साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है और हर कोई यह देखने को उत्सुक है कि यह मेगा कोलैबोरेशन बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाता है। प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में एनटीआर लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्माण माइथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले किया जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com